वर्ष- 03 अंक -11 अप्रैल 2026 मूल्य - 50 रू.

SCG न्यूज

लाईफ वर्सिटी

आतंक का खात्मा
विकास का उदय

Postal Regn. No. C.G./RYP DN/108/2024-26 RNI No. CHHHIN/2023/87466

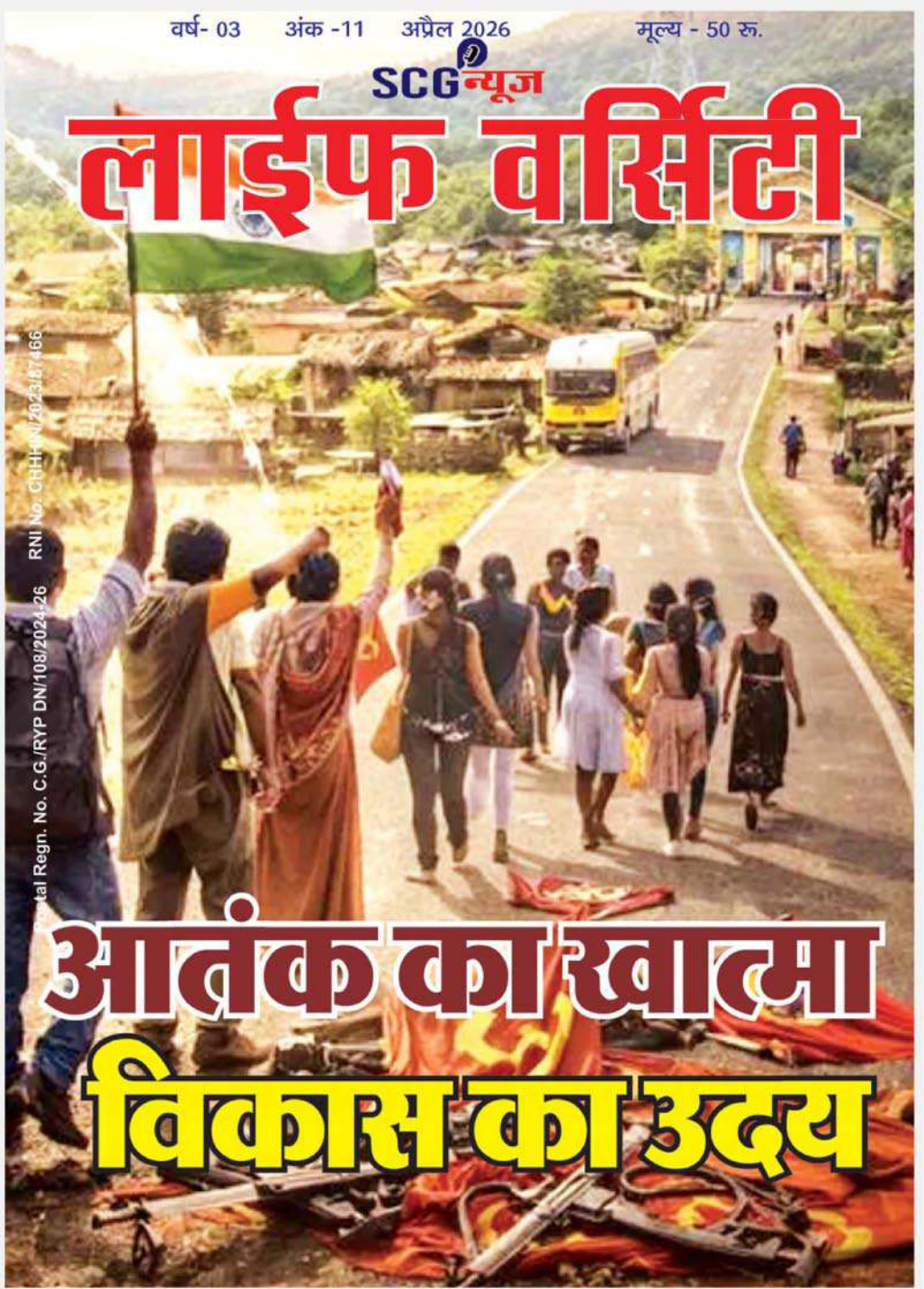

www.phzinfo.com

Positive Health Zone

Integrated Holistic
Health Care System
Unique Wellbeing Center

Holistic Healthcare Team

Our INTEGRATED SERVICES

Holistic Path Of Wellness & Wellbeing

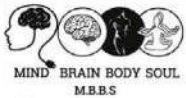

1. **Personal Energy Blueprint at Quantum Veda Lab with Latest Quantum Devices-**
   Aura, Chakra, Biofield, Lifeforce Energy Analysis.

2. **Digital Nadi Parikshan Modern Nadi Veda Pulse -**
   Personality Analysis
   Body Type, Mind Type, Energy Type.

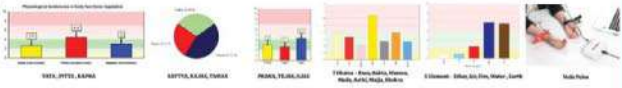

3. **Life Style Clinic**
   Personalised Diet Plan, Lifestyle Plan, Day Plan, Detox Plan as per your Quantum Analysis.

4. **Body Detox & Rejuvenation with Kerala Ayurveda Panchkarma.**

5. **Mind Detox & Stress Management with NLP & Counselling.**

6. **Inner Alingment, Chakra Balancing with PNP Meditation.**

Get In Touch
9109185020, 9109185025

A-41, Amrapali Society,
Near Ganga Diagnostics, Raipur, Chhattisgarh

www.phzinfo.com

सम्पादक
नरेन्द्र कुमार पाण्डेय

प्रबंधक
हर्षित पाण्डेय

सलाहकार मण्डल
डॉ अनिल गुप्ता रायपुर
डॉ उदयभान सिंह चौहान रायपुर
प्रो. डॉ शुभ्रा सान्याल नई दिल्ली
प्रो तपन मोहन्ति ओड़िसा

सलाहकार (मीडिया मार्केटिंग एंड एआई)
भूपेन्द्र सिंग

छत्तीसगढ़ कार्यालय
ए-32, आम्रपाली सोसाइटी, कलर्स मॉल के पीछे, पचपेड़ी नाका
रायपुर (छ.ग.)
मो. 88171-94979

मध्यप्रदेश कार्यालय
अनामिका पाण्डेय
गोकुलधाम बेलौहान टोला,
सामान, रीवा मप्र

प्रतिनिधि
अम्बुज अग्निहोत्री जबलपुर
संजीव पाण्डेय भोपाल
राजेश सिंह बिलासपुर

कानूनी सलाहकार
संजयेंदु पंड्या

परिकल्पना
रजनीकांत पाण्डेय

अंदर के पृष्ठों पर

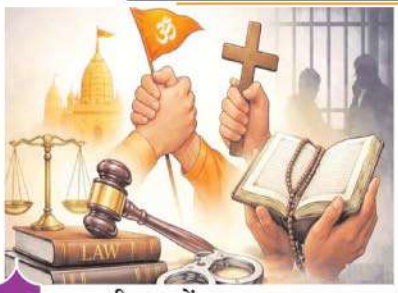

03 छत्तीसगढ़ में नया कानून लागू, धर्मांतरण पर लगेगी लगाम,

8 कभी लालू के सिपाही थे अब मोदी-शाह के भरोसेमंद नेता बने सम्राट चौधरी

6 बस्तर 2.0 की शुरुआतः प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने सौंपा विकास का ब्लूप्रिंट

18 आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं ग्रामीण महिलाएं

13 राजनीति को बदल देगा महिला आरक्षण

25 समस्या केवल 'कितना पानी है' का नहीं, बल्कि 'कैसा पानी है' का

भटके कदमों को नई दिशा 2
बदलाव की बयार 5
गढ़ बचाने और भेदने के तीखे तेवर 9
रजत बंसल बनाए गए जनसंपर्क... 14
'रील सच, रियल भ्रम' 20
सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की महिलाएं 27

SCAN & PAY
UPI ID: 329944413263914@cnrb
लाईफ वर्सिटी के प्रचार–प्रसार में सहयोग करें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बुरहानी प्रिंटर्स, सत्ती बाजार रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, सांई वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979
E-mail : scgnewsraipur@gmail.com | www.scgnews.in

भटके कदमों को नई दिशा

सुकमा में पुनर्वास से विकास की कहानी लिख रही है सरकार

मुख्यमंत्री ने पुनर्वास केंद्र का किया अवलोकन, पुनर्वासितों से किया आत्मीय संवाद

नक्सल आतंक से लंबे समय तक प्रभावित रहे सुकमा में अब शांति, विश्वास और विकास की नई तस्वीर उभर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुकमा जिला मुख्यालय स्थित पुनर्वास केंद्र का दौरा कर वहां संचालित पुनर्वास एवं कौशल विकास गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पुनर्वासित लोगों से आत्मीय संवाद कर उनके अनुभव जाने और उन्हें मुख्यधारा से जुड़कर नया जीवन प्रारंभ करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक जीवन, रोजगार और आगे बढ़ने के समान अवसर देने के लिए दृढ़संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पुनर्वासितों की आंखों में दिखता आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि यदि सही अवसर और मार्गदर्शन मिले, तो हर भटका हुआ कदम नई दिशा और नया जीवन प्राप्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी नक्सल पुनर्वास नीति के चलते सुकमा सहित बस्तर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब तक 2392 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया है, जिनमें से 361 पुनर्वासितों ने नया जीवन प्रारंभ कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल पुनर्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि इन नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, स्थायी रोजगार और समाज में बराबरी का अवसर प्रदान करना है। पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, कपड़ा सिलाई, कृषि उद्यमिता और वाहन चालक जैसे विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक 307 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं मुख्यधारा में लौटे 313 युवाओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा 107 पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं, जिससे वे डिजिटल और संचार माध्यमों से जुड़कर आधुनिक जीवनशैली की ओर अग्रसर हो सकें। विशेष रूप से 115 महिलाएं प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को भी राहत प्रदान करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में 20 तथा जिला प्रशासन द्वारा 95 लोगों को शासकीय सेवा में रोजगार के अवसर दिए गए हैं।

कार्यक्रम के दौरान ग्राम ढोंडरा कोंटा निवासी मौसम संजना, नागारास जगरगुंडा निवासी भरत कुमार हेमला सहित अन्य हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के अंतर्गत 10 नव नियुक्त शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल, राजमिस्त्री किट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की चाबियां तथा पूर्णता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर 25 हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपकर उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने नक्सल पुनर्वास की सफलता की प्रेरणादायक कहानियों को दर्शाती 'बदलते सुकमा की बदलती तस्वीर- पुनर्वास से विकास तक' कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। साथ ही, पुनर्वास केंद्र के कला केंद्र में कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल भौतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक बदलाव का भी प्रतीक है।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने दी मंजूरी

छत्तीसगढ़ में नया कानून लागू, धर्मांतरण पर लगेगी लगाम,

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए नए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 पर राज्यपाल रमेन डेका के हस्ताक्षर के साथ ही कानून लागू हो गया है, जिसके तहत अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े मामलों में सजा 10 से 20 साल तक की जेल और न्यूनतम 10 लाख रुपये जुर्माना तय किया गया है।

वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत झूठ, प्रलोभन, दबाव या कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराना अवैध माना जाएगा और अपराध संज्ञेय व अजमानतीय होंगे।

जिनकी सुनवाई विशेष न्यायालय में होगी। जबकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना अनिवार्य होगा और 30 दिनों तक आपत्ति दर्ज कराने का अवसर रहेगा। इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं।

धर्म परिवर्तन करने से पहले देनी होगी जानकारी

नए कानून के तहत धर्म परिवर्तन करने से पहले संबंधित व्यक्ति को 60 दिन पहले कलेक्टर को आवेदन देना अनिवार्य होगा। साथ ही अनुष्ठान कराने वाले पुजारी, मौलवी या पादरी को भी पूर्व सूचना देनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर इसे अवैध धर्मांतरण माना जाएगा और तत्काल गिरफ्तारी हो सकती है।

अब धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा, जिसके बाद निर्धारित समय-सीमा में सूचना सार्वजनिक की जाएगी और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जांच के उपरांत ही प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता रहे, लेकिन यह परिवर्तन किसी दबाव, प्रलोभन या भय के कारण न हो, इसकी जांच अनिवार्य होगी।

शादी के लिए धर्मांतरण, तो शादी अवैध

कानून में 'लव जिहाद' जैसे मामलों को रोकने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई शादी को शून्य घोषित किया जा सकेगा। इसके अलावा विदेशी फंडिंग और संस्थाओं की भूमिका पर भी सख्ती बरती जाएगी।

धर्मान्तरण के उद्देश्य से किसी विदेशी से मौद्रिक लाभ लेने अथवा देने पर

- 10 से 20 वर्ष का कारावास
- न्यूनतम 20 लाख जुर्माना
- भय, बल, प्रलोभन या मानव तस्करी के माध्यम से धर्मांतरण
- 10-20 वर्ष तक कारावास न्यूनतम 30 लाख जुर्माना

विधेयक में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अब धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा, जिसके बाद निर्धारित समय-सीमा में सूचना सार्वजनिक की जाएगी और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जांच के उपरांत ही प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता रहे, लेकिन यह परिवर्तन किसी दबाव, प्रलोभन या भय के कारण न हो, इसकी जांच अनिवार्य होगी। इस कानून में धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी को हर वर्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें धर्मांतरण से संबंधित जानकारी का विवरण शामिल होगा। ग्राम सभा को भी इस प्रक्रिया में भागीदारी दी गई है।

लाल आतंक के सूर्यास्त के साथ सुकमा में उदय हुआ स्वास्थ्य सेवाओं का सूरज

मेगा स्वास्थ्य शिविर में उमड़ा जनसैलाब

बस्तर के सुदूर अंचलों में कभी लाल आतंक की धमक से सहमे रहने वाले सुकमा जिले की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। दशकों पुराने संघर्ष और भय के बादलों को चीरकर अब यहाँ विकास और खुशहाली की नई किरणें बिखर रही हैं। जिला प्रशासन सुकमा और बेंगलुरु के एनटीआर फाउंडेशन के साझा प्रयासों से आयोजित दो दिवसीय सुपर स्पेशलिटी मेगा स्वास्थ्य शिविर इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अब सुकमा नक्सलवाद की बेड़ियों को तोड़कर स्वस्थ और सशक्त होने की राह पर निकल पड़ा है। मिनी स्टेडियम में विगत 28 और 29 मार्च को आयोजित इस शिविर ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि जहाँ कभी गोलियों की गूँज थी, आज वहाँ सेवा और संकल्प के गीत गाए जा रहे हैं।

लाल आतंक की समाप्ति के इस दौर में जब क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बना है, तब प्रशासन की पहुँच अंतिम छोर के व्यक्ति तक आसान हुई है। प्रदेश के वन मंत्री एवं सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के द्वारा शुभारंभ पश्चात इस मेगा स्वास्थ्य शिविर में उन संवेदनशील और अंदरूनी क्षेत्रों के 3,700 से अधिक ग्रामीण बेखौफ होकर पहुँचे, जो कभी मुख्यधारा से कटे हुए थे। कमिश्नर बस्तर श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित उक्त मेगा स्वास्थ्य शिविर में कुल 6,500 से अधिक लाभार्थियों की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि अब ग्रामीण बंदूकों के साये से निकलकर आधुनिक चिकित्सा और विशेषज्ञ परामर्श पर भरोसा जता रहे हैं। शिविर के दौरान 21 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 40 स्वास्थ्य योद्धाओं की टीम ने इन वनवासियों के लिए देवदूत बनकर काम किया।

शिविर में केवल सामान्य बीमारियों का ही नहीं, बल्कि कैंसर, हृदय रोग और न्यूरोलॉजी जैसी गंभीर समस्याओं का भी विशेषज्ञ उपचार किया गया। नक्सलवाद के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहे बुजुर्गों के लिए 989 चश्मों का वितरण किया गया, जिससे उनकी धुंधली दुनिया एक बार फिर रोशनी से भर उठी। वहीं 1,500 बच्चों का व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण कर आने वाली पीढ़ी को कुपोषण और बीमारियों से मुक्त करने का संकल्प लिया गया। विशेष रूप से 85 महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग और 2,300 आभा आईडी का निर्माण इस बात का प्रतीक है कि सुकमा अब डिजिटल स्वास्थ्य और सुरक्षा कवच से लैस हो रहा है।

लाल आतंक के खात्मे के बाद सुकमा का यह बदलाव पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल है। यह शिविर केवल एक चिकित्सकीय आयोजन नहीं था, बल्कि शासन-प्रशासन के प्रति जनता के अटूट विश्वास का उत्सव था। 153 आयुष्मान कार्डों का मौके पर निर्माण यह सुनिश्चित करता है कि अब सुदूर अंचल का गरीब से गरीब व्यक्ति भी पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सुकमा आज नक्सलवाद की पहचान को पीछे छोड़कर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक रोल मॉडल बनकर उभर रहा है, जहाँ हर चेहरा मुस्कुरा रहा है और हर कदम एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ रहा है।

बदलाव की बयार - पानी के लिए नहीं भटकेंगे ग्रामीण, 117 घरों में पहुंचा अमृत

जहाँ था डर और प्यास वहाँ अब विकास

कभी नक्सल भय और पेयजल संकट से जूझता सुकमा जिले का दूरस्थ ग्राम लखापाल आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। वर्षों तक जहां ग्रामीणों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वहीं अब हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। यह बदलाव केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन और छत्तीसगढ़ शासन की नियद नेल्लनार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और कलेक्टर श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन में कोंटा विकासखंड के घोर नक्सल प्रभावित ग्राम लखापाल में विकास की वह रोशनी पहुंची है, जिसकी यहां वर्षों से प्रतीक्षा थी।

जहां पानी के लिए थी जद्दोजहद, अब घर-घर बह रहा अमृत

जिला मुख्यालय सुकमा से लगभग 88 किलोमीटर दूर स्थित लखापाल गांव लंबे समय तक नक्सल समस्या और पेयजल संकट की दोहरी मार झेलता रहा। गांव के 117 परिवार पानी के लिए बोरिंग, कुएं और एक छोटे नाले पर निर्भर थे। गर्मी के दिनों में जलस्तर इतना नीचे चला जाता था कि ग्रामीणों को बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। महिलाओं और बच्चों को कई बार दूर-दराज़ से पानी लाना पड़ता था। समय और मेहनत के साथ-साथ बीमारियों का खतरा भी लगातार बना रहता था।

72 लाख की योजना ने बदल दिया गांव का भविष्य

सुकमा जिले के कार्यपालन अभियंता श्री विनोद कुमार राम ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत लखापाल में 72.01 लाख रुपये की लागत से 4 सोलर पंप टंकी स्थापित की गई। इसके माध्यम से गांव में 117 घरेलू नल कनेक्शन दिए गए। गांव की कुल जनसंख्या 465 है, और अब हर परिवार को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

महिलाओं की आंखों में राहत, चेहरे पर मुस्कान

गांव की महिला श्रीमती लखे तेलाम भावुक होकर बताती हैं कि पहले पानी के लिए बहुत परेशानी होती थी। नाले और बोरिंग से पानी लाना पड़ता था। कई बार मौसमी बीमारी हो जाती थी। महुआ बीनकर लौटने के बाद पानी लेने जाना बहुत मुश्किल होता था। अब नल से घर में ही दिनभर पानी मिलता है। हम बहुत खुश हैं। शासन की योजना बहुत अच्छी है। उनकी बातों में केवल राहत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की उम्मीद झलकती है।

डर के साये से विकास की राह तक

गांव के निवासी तेलाम बुधु बताते हैं कि पहले लखापाल में भय का माहौल था। हमारा गांव पहले नक्सल समस्या से प्रभावित था। लोग खौफ़ में जीते थे। बिजली, पानी और सड़क की समस्या थी। गांव में पहले नक्सलियों की मीटिंग होती थी। गांववालों से पैसा और चावल-दाल जमा कराया जाता था। लेकिन अब बदलाव आ गया है। अब पंचायत की मीटिंग ग्राम विकास के लिए होती है। बिजली, पानी, राशन और सड़क की सुविधा मिल रही है। उनके शब्द साफ कहते हैं अब गांव में डर नहीं, विकास की चर्चा होती है।

स्वच्छ जल से स्वास्थ्य में सुधार, बीमारी में कमी

जल जीवन मिशन के लागू होने के बाद लखापाल में सिर्फ पानी की सुविधा नहीं आई, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अब जलजनित बीमारियों में कमी आई है और स्वच्छ पेयजल के कारण ग्रामीणों की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आया है।

अब सब्जी-बाड़ी से आत्मनिर्भरता की ओर गांव

नल जल योजना से पानी मिलने के बाद ग्रामीणों ने खेती और बाड़ी की ओर कदम बढ़ाया है। अब गांव के लोग अपने घर के आसपास टमाटर, मिर्ची, बरबट्टी, सेमी और खट्ठा भाजी उगा रहे हैं। इससे न केवल घर में सब्जी की व्यवस्था हो रही है, बल्कि बाजार से सब्जी खरीदने का खर्च भी बच रहा है।

कलेक्टर श्री अमित कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्राम लखापाल जैसे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना प्रशासन की बड़ी उपलब्धि है। इससे ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले के प्रत्येक गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर विकास की रोशनी हर क्षेत्र तक पहुंचाई जाएगी।*

ग्रामीणों ने जताया मुख्यमंत्री और प्रशासन के प्रति आभार

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता। घर में नल से पानी मिल रहा है, जिससे जीवन आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक हुआ है।

लखापाल बना उदाहरण- विकास हर कोने तक पहुंच रहा है

जल जीवन मिशन ने यह साबित कर दिया है कि जब सरकार की योजनाएं ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर उतरती हैं, तो नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में भी विकास की नई रोशनी पहुंचती है। आज लखापाल गांव केवल पानी की सुविधा नहीं पा रहा बल्कि वह भय से मुक्त होकर आत्मनिर्भरता और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने पीएम मोदी को दिया आमंत्रण

बस्तर 2.0 की शुरुआत: प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने सौंपा विकास का ब्लूप्रिंट

बस्तर के लिए 360ए प्लान-टूरिज्म, स्टार्टअप, इंफ्रा और इनोवेशन पर फोकस

पीएम का बस्तर दौरा बनेगा टर्निंग पॉइंट, बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात

बस्तर समेत पूरे राज्य में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और अब शांति स्थापित है। शिक्षा व स्वास्थ्य सुधार के तहत नए एजुकेशन सिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जबकि इंद्रावती नदी पर बैराज, रेल लाइन और एयरपोर्ट विस्तार से कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने न केवल नक्सलवाद के अंत के बाद प्रदेश में आई शांति के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया, बल्कि बस्तर के समग्र विकास का एक विस्तृत और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट भी सौंपा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का आमंत्रण दिया, जहां उनकी मौजूदगी में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि बस्तर समेत पूरे राज्य में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और अब शांति स्थापित है। शिक्षा व स्वास्थ्य सुधार के तहत नए एजुकेशन सिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जबकि इंद्रावती नदी पर बैराज, रेल लाइन और एयरपोर्ट विस्तार से कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ब्लूप्रिंट के जरिए बस्तर में अब विकास, रोजगार और बेहतर सुविधाओं का नया दौर शुरू होगा।

मुख्यमंत्री ने अपने विकास दस्तावेज़ में उल्लेख किया कि एक दशक पहले प्रधानमंत्री द्वारा बस्तर के लिए देखा गया शांति और

विकास का सपना अब जमीन पर साकार हो रहा है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब लोगों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद और विकास की नई चमक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से बस्तर को नई दिशा और गति मिलेगी, जिससे क्षेत्र में विश्वास और उत्साह बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विकास ब्लूप्रिंट 'सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटेट, एम्पावर और एंगेज' रणनीति पर आधारित है। इसके तहत बस्तर में बुनियादी सुविधाओं को तेजी से विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों के व्यापक जाल के माध्यम से दूर-दराज के गांवों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों को 2027 तक पूरा करने के साथ-साथ नई 228 सड़कों और 267 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा 61 नई परियोजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग भी की गई है।

ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की योजना है। हर घर तक बिजली पहुंचाने के कार्य तेज होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 45 पोटा केबिन स्कूलों को स्थायी भवनों में बदला जाएगा। युवाओं के लिए 15 स्टेडियम और 2 मल्टीपर्पज हॉल बनाए जाएंगे, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार और डॉक्टरों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनाए जा रहे हैं।

कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर दो बड़े प्रोजेक्ट देउरगांव और मटनार में स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे 31,840 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। यह परियोजनाएं बस्तर की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

आजीविका और आय बढ़ाने के लिए सरकार ने तीन वर्षीय योजना तैयार की है, जिसका लक्ष्य 2029 तक 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करना है। 'नियद नेल्ला नार 2.0' योजना के तहत अब अधिक जिलों को जोड़ा जा रहा है, जिससे विकास का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचेगा। 10 जिलों में शुरू की गई यह योजना अब 7 जिलों और 3 नए जिलों (गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई) तक विस्तारित हो रही है।

'अंजोर विजन 2047' और 'विकसित भारत@2047' के तहत स्टार्टअप नीति भी लागू की गई है, जिसमें 2030 तक 5,000 स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य है। पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, एडवेंचर टूरिज्म, कैनोपी वॉक और ग्लास ब्रिज जैसी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन क्षेत्र को नई पहचान दे रहे हैं। वहीं, एक लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 40 हजार को रोजगार भी मिल चुका है।

नक्सलवाद से मुक्त बस्तर के विकास के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री के सामने जो कार्ययोजना प्रस्तुत की, उसमें 'बस्तर मुन्ने' (अग्रणी बस्तर) कार्यक्रम एक अहम पहल है। इस कार्यक्रम के तहत हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे, जहाँ अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे दिया जाएगा, जरूरी दस्तावेज वहीं बनाए जाएंगे और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाएँ आसानी से पहुँचें और बस्तर तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़े।

प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान जिन प्रमुख परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की योजना है, उनमें रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन, जगदलपुर एयरपोर्ट का विस्तार, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज, जगरगुंडा और ओरछा में एजुकेशन सिटी जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं।

ये परियोजनाएं बस्तर को शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बेल मेटल निर्मित 'माता कौशल्या के राम' कलाकृति की भेंट

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बेल मेटल निर्मित 'माता कौशल्या के राम' कलाकृति की भेंट

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती बेल मेटल से निर्मित 'माता कौशल्या के राम' की अद्वितीय कलाकृति भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ वह पावन धरा है, जहाँ भगवान श्रीराम का ननिहाल स्थित है और यह भूमि प्रभु श्रीराम से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भेंट की गई यह कलाकृति प्रदेश की आस्था, परंपरा और सृजनशीलता का सजीव प्रतिरूप है, जो जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्पकौशल को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित 'श्री रामलला दर्शन योजना' के माध्यम से प्रदेश के हजारों श्रद्धालु अयोध्या धाम के दर्शन कर रहे हैं, जिससे आस्था और श्रद्धा को जन-जन तक जोड़ने का कार्य निरंतर हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रभु श्रीराम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार सेवा, संस्कार और सुशासन के पथ पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करता रहेगा।

कभी लालू के सिपाही थे अब मोदी-शाह के भरोसेमंद नेता बने सम्राट चौधरी

भाजपा के सम्राट चौधरी बनाए गए बिहार के नए मुख्यमंत्री

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है. सम्राट चौधरी अब राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आरजेडी से बीजेपी तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है और कम समय में ही वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद नेता बनकर उभरे हैं.

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है. सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और वे राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनकी राजनीति का सफर काफी दिलचस्प रहा है. एक समय वे लालू प्रसाद यादव की टीम का हिस्सा थे और आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं.

सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ. उनके पिता शकुनी चौधरी और माता पार्वती देवी हैं. वे दो बार परबत्ता से विधायक रहे हैं और दो बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं. उन्हें प्रशासनिक और विधायी कार्यों का अच्छा अनुभव है. वे दो बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं. 2024 में उन्हें वित्त मंत्री की जिम्मेदारी मिली, वहीं नवंबर 2025 में गृह मंत्रालय का भी कमान सौंपा गया.

बीजेपी में तेजी से बढ़ा कद

ओबीसी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी कुशवाहा (कोइरी) समाज से ताल्लुक रखते हैं. वे 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे. उसी साल नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए थे, तब सम्राट को पंचायती राज मंत्री बनाया गया था.

सिर्फ 9 साल में उन्होंने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया. अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा, तब बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया. उन्होंने इस जिम्मेदारी को मजबूती से निभाया.

आरएसएस बैकग्राउंड नहीं, फिर भी संगठन में मजबूत पकड़

सम्राट चौधरी उन नेताओं में हैं, जिनका आरएसएस बैकग्राउंड नहीं है. उनके पिता समता पार्टी से जुड़े रहे और नीतीश कुमार व लालू प्रसाद यादव दोनों के करीबी माने जाते थे. सम्राट चौधरी ने 1990 में राजनीति में कदम रखा और 1995 में 89 दिनों के लिए जेल भी गए थे.

जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार से मतभेद हुआ था, तब सम्राट चौधरी ने कुछ विधायकों के साथ मांझी का समर्थन किया था. इससे उनकी अलग पहचान बनी.

'मुरेठा' वाली प्रतिज्ञा से चर्चा में

सम्राट चौधरी तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने तक पगड़ी (मुरेठा) नहीं उतारने की प्रतिज्ञा ली थी. वे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में पगड़ी बांधे नजर आते थे. इस पर कई नेताओं ने तंज भी कसा.

राम मंदिर दर्शन के बाद उतारी पगड़ी

जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में लौटे और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने, तब उन्होंने राम मंदिर अयोध्या में दर्शन के बाद अपनी पगड़ी उतारी. इसी के बाद से पार्टी नेतृत्व का उन पर भरोसा और मजबूत हुआ.

मोदी-शाह के भरोसेमंद नेता कैसे बने?

बीजेपी ने जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब पार्टी को बिहार में मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई. उन्होंने संगठन को मजबूती दी और लगातार एक्टिव राजनीति में बने रहे. यही वजह है कि आज वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरों में शामिल हैं.

सामाजिक समीकरण में भी फिट बैठते हैं सम्राट

सम्राट चौधरी कुशवाहा (कोइरी) समाज से आते हैं, जिसकी बिहार में अच्छी खासी आबादी है. ऐसे में वे सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी एनडीए के लिए मजबूत चेहरा माने जाते हैं. बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है. अब देखना होगा कि वे अपने अनुभव और संगठनात्मक क्षमता के दम पर राज्य को किस दिशा में ले जाते हैं.

विधानसभा चुनाव '26 पश्चिम बंगाल

गढ़ बचाने और भेदने के तीखे तेवर

इन चुनावों के दौर में सबसे रोमांचक मुकाबला पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। पूरब में यह राज्य भाजपा की चुनावी जीत के सामने बड़ी बाधा बनकर खड़ा है। 2011 में तीन दशकों के वामपंथी शासन के अंत के बाद ममता बनर्जी सत्ता में आईं, तब से राज्य का राजनैतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। 2011 में एक भी सीट न जीत पाने वाली भाजपा के राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरने तक राज्य की राजनीति में जबरदस्त बदलाव आया है। उसका स्वरूप और समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। राज्य में कभी मुख्य ताकतें रहीं वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस अब अपने वजूद और प्रासंगिकता की लड़ाई लड़ रही हैं। अब मुख्य मुकाबला दो पार्टियों तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच रह गया है।

ये दोनों प्रमुख पार्टियां 294 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही हैं। इन दोनों की ही रणनीति बहुमत का आंकड़ा (148 सीटें) पार करने की है। 2021 के चुनावों में तृणमूल ने 215 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की थी। भाजपा को 77 सीटें मिली थीं और आइएसएफ ने एक सीट जीती थी। कांग्रेस और माकपा का खाता भी नहीं खुल पाया था। पहली बार ये दोनों एक भी सीट जीतने में नाकाम रहीं। 2021 के चुनावों ने विपक्षी दलों की रणनीति और स्वरूप में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया, जिससे बंगाल का राजनैतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। यह स्थिति 2016 के चुनावों से बिल्कुल विपरीत थी, जब तृणमूल ने 211 सीटें जीती थीं, कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं, माकपा के खाते में 26 सीटें आई थीं, जबकि भाजपा सिर्फ 3 सीटें ही पा सकी थी।

राज्य में कभी मुख्य ताकतें रहीं वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस अब अपने वजूद और प्रासंगिकता की लड़ाई लड़ रही हैं। अब मुख्य मुकाबला दो पार्टियों तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच रह गया है।

बेशक, मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच होगा। शुभेंदु इस बार दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी परंपरागत नंदीग्राम के अलावा वे कोलकाता में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को चुनौती देने जा रहे हैं। यह भाजपा की आक्रामकता और पिछली बार से उलट नजारा है, जब ममता नंदीग्राम शुभेंदु को चुनौती देने पहुंच गई थीं और बेहद मामूली अंतर से हारी थीं।

लेकिन इन चुनावों में कई ऐसे चेहरे भी हैं, जो मैदान में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। तृणमूल के शीर्ष नेता फिरहाद हकीम, ब्रात्य बसु, चंद्रिमा भट्टाचार्य, अरूप राय, सुजीत बोस और शशि पांजा का मुकाबला भाजपा के शंकर घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक लाहिड़ी, नीरज तमांग जिम्बा और अन्य नेताओं से होगा। तृणमूल के महासचिव तथा सांसद अभिषेक बनर्जी, और भाजपा के नए अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी चुनाव प्रचार और रणनीतियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

प्रमुख चुनावी मुद्दे

एसआइआर और चुनाव आयोग- पिछले कुछ महीनों में ममता बनर्जी चुनाव आयोग की 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (एसआइआर) मुहिम के खिलाफ सबसे मुखर और मजबूत आवाज बनकर उभरी हैं। आयोग पर उनका लगातार हमला और इस मुहिम को लेकर पार्टी की चिंताओं को जिस आक्रामकता से उन्होंने उठाया, वह सुर्खियों में बना रहा और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ खुद अपनी दलील रखने पहुंचीं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी एसआइआर की स्थिति उलझी हुई है, क्योंकि करीब 60 लाख लोग संदिग्ध सूची में डाले गए हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ने के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। चुनावों से पहले एसआइआर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए मुख्य मुद्दा बनकर उभरा है।

यही नहीं, आयोग ने चुनाव की तारीखों (दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई को नतीजे) के ऐलान के फौरन बाद मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और तमाम जिलों के डीएम तथा एसपी सहित 50 से अधिक अधिकारियों के दनादन तबादले कर दिए। इसे भी ममता चुनाव आयोग को भाजपा के लिए मैदान बनाने के खातिर आड़े हाथों ले रही हैं। तृणमूल नेता यह भी सवाल उठा रहे हैं कि असम में ऐसे तबादले आयोग ने नहीं किए,

जिससे साफ हो जाता है कि आयोग भाजपा के एजेंडे पर चल रहा है। उसके कुछ ही दिन पहले केंद्र ने वहां के राज्यपाल को बदल दिया और आर.एन.रवि को लाया गया, जिनका तमिलनाडु में कार्यकाल काफी विवादास्पद रहा है। ममता तो इन सबको भाजपा के खिलाफ मुद्दा बना ही रही हैं, यह दिखा रहा है भाजपा किस कदर हर हाल में जीतने की उतावली में है।

कल्याणकारी योजनाएं- ममता बनर्जी की कल्याणकारी योजनाओं ने पिछले कुछ साल में उनके मुख्य वोट बैंक को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच। राज्य सरकार ने हाल में पेश अंतरिम बजट में नई 'युवा साथी योजना' और 'लक्ष्मी भंडार' की राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की। उसके बाद भाजपा ने भी केंद्र की योजनाओं और कुछ नए वादों का सहारा लिया है। बंगाल के अपने हालिया दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का ज़िक्र किया और रोजगार सृजन, जन कल्याण और समग्र विकास को लेकर भाजपा के नजरिए का हवाला दिया।

घुसपैठ-भाजपा के लिए घुसपैठ का हमेशा से ही मुख्य मुद्दा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने फिर दोहराया है कि वे वोटर लिस्ट को साफ करना चाहते हैं और राज्य को अवैध घुसपैठियों—खासकर बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों—से मुक्त कराना चाहते हैं। भाजपा अवैध घुसपैठ और इससे राज्य की आबादी के स्वरूप (डेमोग्राफी) में होने वाले बदलाव के खतरे को मुद्दा बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री सीएए के जरिए बंगाल में खासकर मतुआ समुदाय को नागरिकता देने की बात दोहरा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके खास फायदे कागजात के रूप में नहीं दिखे हैं। तृणमूल उसे नौटंकी और भाजपा की विभाजनकारी नीति बता रही है।

महिला मुद्दे- ममता बनर्जी पिछले कई साल से तृणमूल के घोषणापत्रों और नीतियों में महिलाओं को प्राथमिकता देने पर लगातार जोर देती रही हैं। इसी का नतीजा है कि संसद में तृणमूल की महिला भागीदारी 40 प्रतिशत से ज्यादा है। फिर भी आरजी कर अस्पताल बलात्कार कांड, और दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज बलात्कार जैसे मामलों ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा ने महिलाओं की सुरक्षा को अपने चुनावी वादों के केंद्र में रखा है। भाजपा ने खासकर आरजी कर बलात?कार कांड के पीड़ित परिवारों को चुनाव में खड़ा भी किया है। दूसरी ओर, तृणमूल ने देश के अन्य हिस्सों में हुई ऐसी ही घटनाओं का ज़िक्र करके भाजपा को 'मूल रूप से महिला-विरोधी' पार्टी बताया है।

सांस्कृतिक पहचान

तृणमूल लगातार भाजपा को 'बाहरी पार्टी' बताती रही है और बंगाल की संस्कृति और प्रतीकों को अपना बनाने की भाजपा की कोशिशों का विरोध करती रही है। ममता और तृणमूल के नेता कहते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर और सुभाष बोस के नेतृत्व में बंगाल में राष्ट्रवाद की सोच भाजपा के 'हिंदुत्व' के बिल्कुल विपरीत है। हालांकि, भाजपा के नेताओं के हालिया भाषणों में बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों, कलाकारों और प्रतीकों का जिक्र खूब होता है। पार्टी के नेताओं ने बंगाल के सांस्कृतिक परिवेश और उसकी समृद्ध विरासत को फिर से संवारने का वादा किया है। बहरहाल, लड़ाई दिलचस्प है और जो भी जीते उसका बंगाल ही नहीं, देश की सियासत पर भी ऐतिहासिक असर पड़ने वाला है।

नक्सल मुक्त भारत के बाद 'ऑपरेशन द एंड' शुरू

नक्सलियों के अर्थतंत्र और स्मारकों पर बुलडोजर एक्शन

नक्सल मुक्त भारत का ऐलान हो चुका है, अब केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसी और सुरक्षाबल मिलकर नक्सलियों के आर्थिक तंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने के साथ-साथ नक्सलियों की विचारधारा को समाप्त करने का अभियान तेजी से शुरू किया है, नक्सलियों की अर्थ तंत्र को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान अबूझमाड़ के जंगलों में शुरू किया है, इसी इलाके में नक्सलियों में अपने जो स्मारक बना रखे थे. उनको भी तोड़ा जा रहा है, पिछले एक महीने की अगर बात करें तो सुरक्षा बलों ने बस्तर के इलाके में 12 करोड़ से ज्यादा मूल्य के रुपये और सोना बरामद किए हैं, जिसमें 6 करोड़ 75 लाख रुपये नगद और 8 किलोग्राम सोना नक्सलियों के डंप से बरामद किया गया है.

केंद्र और राज्य सरकारों ने 'नक्सल मुक्त भारत' के ऐलान के बाद अब नक्सलियों की जड़ों को काटने के लिए 'ऑपरेशन द एंड' छेड़ दिया है. पिछले एक महीने में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के गुप्त ठिकानों से 12 करोड़ की संपत्ति और 300 से ज्यादा स्मारक ध्वस्त कर उनकी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया है.

नक्सल मुक्त भारत का ऐलान हो चुका है, अब केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसी और सुरक्षाबल मिलकर नक्सलियों के आर्थिक तंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने के साथ-साथ नक्सलियों की विचारधारा को समाप्त करने का अभियान तेजी से शुरू किया है, नक्सलियों की अर्थ तंत्र को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान अबूझमाड़ के जंगलों में शुरू किया है, इसी इलाके में नक्सलियों में अपने जो स्मारक बना रखे थे. उनको भी तोड़ा जा रहा है, पिछले एक महीने की अगर बात करें तो सुरक्षा बलों ने बस्तर के इलाके में 12 करोड़ से ज्यादा मूल्य के रुपये और सोना बरामद किए हैं, जिसमें 6 करोड़ 75 लाख रुपये नगद और 8 किलोग्राम सोना नक्सलियों के डंप से बरामद किया गया है. यहां पर नक्सलियों ने ये रुपये नक्सलवाद फैलाने के लिए जमा कर रखे थे. अब जब की देश के विभिन्न इलाकों से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है ऐसे में सुरक्षा बल नक्सलियों के गढ़ में जाकर के उनके हथियारों के डंप रूपए- पैसे सोना चांदी यह तमाम चीज ढूंढने में जुटी हुई है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर नक्सलियों ने अपनी सुरक्षित राजधानी बना रखी थी.

जानकारी मिली है कि नक्सलियों के करीब 300 से ज्यादा स्मारकों को सुरक्षा बलों ने पिछले एक से दो महीने के अंदर नष्ट किया है, स्मारकों को नष्ट करने के पीछे का मकसद ये है कि नक्सली विचारधारा को पूरी तरीके से अबूझमाड़ के जंगलों से खत्म कर देना है.

यही वजह है इन तमाम इलाकों में बुलडोजर के जरिए अभियान सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहा है. DRG/STF/CoBRA/बस्तर फाइटर्स/CRPF/BSF/ITBP/SSB/CAPF ने स्थानीय प्रशासन तथा अन्य सभी हितधारकों के साथ समन्वित प्रयास करते हुए असंभव को संभव कर दिखाया है.

बस्तर संभाग में एक महीने में 170 माओवादी कैडरों की मुख्यधारा में वापसी- विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्यागकर समाज के साथ जुड़ने का निर्णय लिया. पिछले एक महीने में 343 से अधिक घातक हथियार बरामद- AK-47, INSAS, SLR, BGL लांचर और LMG जैसे हथियारों की बड़ी बरामदगी ने माओवादी सैन्य क्षमता को लगभग समाप्त कर दिया है.

12 करोड़ से अधिक नकदी की बरामद

पिछले एक महीने में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के डंप से भारी आर्थिक संसाधन बरामद किए है- पिछले 31 दिनों में रू. 6.75 करोड़ नकद तथा 8 किलोग्राम सोना (रू.12 करोड़ से अधिक मूल्य) की बरामदगी माओवादी

तंत्र के आर्थिक आधार के कमजोर होने का स्पष्ट संकेत है. डंप रिकवरी में ऐतिहासिक उपलब्धि- नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में एक ही महीने की अवधि में इतनी बड़ी नकदी और सोने की बरामदगी एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान है.

उधर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने नक्सल-विरोधी अभियान में नक्सली अर्थ तंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक समर्पित विभाग की स्थापना की है, जिसने 108 मामलों की जांच की और 87 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए, जिससे त्वरित अभियोजन के जरिए नक्सलवादी संगठनात्मक संरचना को काफी कमजोर कर दिया गया, इसके साथी शहरों में रह रहे नक्सलियों के मददगारों के अर्थतंत्र को भी पूरी तरीके से एनआईए ने ध्वस्त किया है.

300 से ज्यादा स्मारकों पर एक्शन

ग्राउंड पर जाकर के हमने तमाम लोकेशन पर देखा है कि अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों ने जो अपने नक्सली विचारधारा को पनपनाने के लिए नक्सली ट्रेनिंग सेंटर के पास बड़े-बड़े वैचारिक स्मारक बना रखे थे. इन स्मारकों को सुरक्षा बलों ने बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया है. इन पर बुलडोजर प्रहार ये दिखाता है कि नक्सलियों के दिल और उनके दिमाग पर उनकी विचारधारा को पूरी तरीके से ध्वस्त सरकार के द्वारा किया जा रहा है.

अब तक की जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन के जरिए नक्सलियों के 300 से ज्यादा विचारधारा को पुष्पित और प्रज्वलित करने वाले स्मारकों को अबूझमाड़ की घने जंगलों में ध्वस्त किया गया है. देशभर में नक्सलियों की स्मारकों को ध्वस्त करने का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. ग्राउंड से जो हमें आंकड़े मिले हैं. उसके मुताबिक, जिसके तहत महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में दोनों राज्यों में मिलाकर अब तक 300 से ज्यादा नक्सली मॉन्यूमेंट्स ध्वस्त किए गए हैं. सबसे ज्यादा कार्रवाई वर्ष 2026 में हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 200 और महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा नक्सली स्मारकों (मॉन्यूमेंट्स) तोड़े गए.

हथियार, उनके डंप तथा IED भारी मात्रा में पकड़े गए... नक्सली इलाके के रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से नक्सलियों ने अलग-अलग पहाड़ी इलाकों की गुफाओं में भारी मात्रा में आईईडी रॉकेट लांचर बनाने की फैक्ट्रियां बंदूक बनाने के लिए देसी स्टाइल मशीन की लगा रखी थी, जिनको की अब लगातार सुरक्षा बल नष्ट कर रहे हैं. आंकड़ों की अगर बात करें तो वर्ष 2024 से 2026 की अवधि के दौरान नक्सलवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सलियों के डंप ढूंढने के अभियानों में बड़ी सफलता हासिल हुई है.

इस दौरान नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं. वर्ष 2024-26 की अवधि में नक्सलियों के कब्जे से AK-47, SLR, INSAS, .303 राइफल और BGL लॉन्चर सहित कुल 1031 हथियार बरामद किए गए.

दूसरी ओर इस अवधि में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों का एक भी हथियार लूटने में सफल नहीं हो सके जो सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. नक्सलियों द्वारा जंगल और पहाड़ी इलाकों में लगाए गए इश्वइ (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) को खोजने और निष्क्रिय करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

इस विशेष अभियान के तहत वर्ष 2025 में सबसे अधिक 894 IED बरामद और निष्क्रिय किए गए.

निष्कर्षइन अभियानों से साफ है कि सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार सफल रहा है, हथियारों की बरामदगी बढ़ी है और IED निष्क्रिय करने में भी बड़ी सफलता मिली है, जबकि नक्सलियों सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने में काफी हद तक नाकाम रहे हैं.

20 अलग-अलग टीमें तैनात

गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार कि नक्सली इलाके में नक्सलियों के विस्फोटकों, जिनको की गुफाओं में छुपा रखा है, उसके लिए अलग-अलग सिक्योरिटी फोर्सेज की विशेष 20 से अधिक टीमें अलग-अलग राज्यों के लिए तैयार की गई है, इन टीमों में बमनिरोधक दस्ते के साथ-साथ आधुनिक विस्फोटक ढूंढने की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं डॉग स्क्वायड टीम, जिसमें बेल्जियम मेलानॉइस किस्म के डॉग के साथ-साथ देसी मोहदुल डॉग को भी इश्वइ विस्फोटक ढूंढने में किया जा रहा है. मकसद ये है कि ऑपरेशन द एंड के तहत पूरी तरीके से नक्सली इलाके को हथियार और विस्फोटक से मुक्त करना है.

बस्तर में ऐतिहासिक परिवर्तन

नक्सलियों के काल पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राज पी पिछले कई सालों से नक्सली इलाके में तैनात हैं और एक बहुत बड़ा श्रेय इनको नक्सली मुक्त भारत में दिया जाएगा. आजतक से बातचीत में उन्होंने कहा कि मिशन 2026 के तहत बस्तर आज एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. लंबे समय तक हिंसा और भय के साये में रहा ये क्षेत्र अब शांति, विश्वास और विकास की नई दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है. सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन और बस्तर की जनता के संयुक्त संकल्प ने नक्सल-मुक्त बस्तर के लक्ष्य को लगभग साकार कर दिया है.

राजनीति को बदल देगा महिला आरक्षण

पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने अचानक नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) के तहत संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन से संबंधित तैयारी शुरू की. उसने इसके लिए विपक्ष से सहयोग मांगा है. बताया यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जायेगा. इसमें कई सारे कदम उठाये जाने की बात कही गयी है. जैसे–संविधान संशोधन से लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाने वाली हैं, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जायेंगी.

इसके अलावा, सरकार ने परिसीमन को 2026–27 के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर कराने का फैसला किया है. इसके पीछे तर्क यह है कि नयी जनगणना होने और उसका आंकड़ा आने में इतना समय लग जायेगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक परिसीमन नहीं हो पायेगा. एक और प्रस्ताव यह है कि संशोधन से राज्यों में सीटों की वृद्धि का अनुपात नहीं बदलेगा. जबकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि कम जनसंख्या होने के कारण दक्षिण भारत के राज्यों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

इस कारण दक्षिण के नेता क्षुब्ध थे. लेकिन नये प्रस्ताव के मुताबिक, परिसीमन से उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर अगर 120 हो जायेंगी, तो तमिलनाडु में भी लोकसभा सीटों में वृद्धि इसी अनुपात में होगी. परिसीमन के मुद्दे पर लंबे समय से उत्तर बनाम दक्षिण का न सिर्फ द्वंद्व छिड़ा हुआ था, बल्कि दक्षिण के राज्यों को लगता था कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने का उन्हें दंड दिया जा रहा है, जबकि ज्यादा आबादी वाले उत्तर भारत के राज्यों को परिसीमन के जरिये बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा. लेकिन नये प्रस्ताव में यह आशंका दूर हो गयी है.

दरअसल, परिसीमन मुद्दे पर एनडीए में भाजपा के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू तक का रवैया नाराजगी भरा था, और वैसे में, दक्षिण भारत में भाजपा के लिए अपना विस्तार कर पाना कठिन होता, इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराकर दक्षिण की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश है. दरअसल, 19 सितंबर, 2023 को जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) संसद से पारित हुआ था, तब इसे जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन और 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की घोषणा की गयी थी. लेकिन अब सरकार ये दोनों कार्य संविधान संशोधन के जरिये करना चाहती है. संविधान संशोधन के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है. इसके अलावा, आधे राज्यों को इसे पारित कराना होगा. बेशक मौजूदा राजनीतिक माहौल में इसे पारित कराना आसान नहीं है. लेकिन विपक्षी दल महिला आरक्षण का विरोध भी नहीं कर पायेंगे.

अगर संसद के विशेष सत्र में इस पर मुहर लग जाती है, तो फिर परिसीमन आयोग बैठेगा, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले वर्ष तक महिला आरक्षण लागू हो जायेगा. हालांकि यह सवाल उठाया जा रहा है कि महिला आरक्षण को अगर 2011 की जनगणना और परिसीमन के आंकड़ों पर ही लागू करना था, तो इसे पहले भी लाया जा सकता था. लेकिन सरकार अब अचानक यह कदम उठाने जा रही है, तो कुछ सोच-समझकर ही उठा रही होगी. दरअसल, अगले साल तीन राज्यों–उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ये चुनाव, जाहिर है कि भाजपा और एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं.

अगर अगले साल तक महिला आरक्षण लागू हो जाता है, तो इन तीनों राज्यों में भाजपा को चुनावी लाभ मिलना तय है. फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को इसका लाभ मिलेगा. हालांकि फिलहाल यह प्रस्ताव है, और काफी जटिल भी है. कई प्रश्नों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं. जैसे परिसीमन के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो जायेंगी. लेकिन ये सीटें किस तरह आरक्षित होंगी, इस बारे में अभी कुछ तय नहीं है. सवाल यह भी है कि परिसीमन जब 2011 की जनगणना के आधार पर ही होना है, तो फिर 2026–27 की जनगणना के आधार पर नये सिरे से परिसीमन कराने का क्या औचित्य होगा. फिलहाल लगता है कि पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए सरकार ने यह दांव चला है.

दरअसल युद्ध का लंबा असर रहने वाला है, और हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव भी लंबे समय तक रहेगा. इस कारण आय से लेकर रोजगार तक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में, महिला आरक्षण लागू कर सरकार महिलाओं का एकमुश्त वोट अपने साथ होने की उम्मीद कर सकती है. इस मामले में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए. एक यह कि चुनावों में महिला वोटरों की भूमिका अब पुरुष वोटरों के बराबर या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगी है. इसके अलावा, महिलाओं का बड़ा वर्ग पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ है. ऐसे में, अगर मान लें कि युद्ध के असर से युवा वर्ग सरकार से नाराज हो जाये, तो उसका चुनावी नतीजे पर बड़ा असर पड़ने की आशंका नहीं है. इसके अलावा, परिसीमन चूंकि 2011 के आंकड़े पर ही होना है, ऐसे में, दक्षिण भारत के नेता खुश हैं, और वहां भाजपा को नाराजगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा.

लेकिन इस कदम को सिर्फ चुनावी राजनीति के चश्मे से देखना सही नहीं होगा. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण लागू हो जाता है, तो यह भारतीय राजनीति की एक बड़ी उपलब्धि होगा. हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि महिला आरक्षण के कारण जिन पुरुष राजनेताओं को अपनी सीटें गंवानी पड़ेंगी, वे आरक्षित सीटों पर अपनी महिला रिश्तेदारों को बिठा सकते हैं. और बहुत संभव है कि इसे राजनीतिक बुराई के तौर पर ही देखा जाये.

लेकिन पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिला आरक्षण लागू होने के बाद हमने देखा है कि भले ही अनेक जगहों पर वास्तविक ताकत अब भी महिला प्रमुखों के पतियों के पास ही हो, लेकिन महिला आरक्षण के कारण बड़ी संख्या में स्त्रियों में जागृति और आत्मविश्वास की भावना आयी है. और अब वे राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में अपनी जगह लेने के लिए तैयार हैं. इस लिहाज से महिला आरक्षण भारतीय राजनीति को बदलने के साथ-साथ उसमें नयी ऊर्जा भर सकता है. संसद और विधानमंडलों में महिलाओं की संख्या बढ़ने पर वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आजीविका जैसे मुद्दों पर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी, जिसका समाज पर निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा.

रजत बंसल बनाए गए जनसंपर्क आयुक्त, सीएम सचिवालय में विशेष सचिव की भी जिम्मेदारी,

आईएएस अफसर रजत कुमार को सरकार ने न केवल जनसंपर्क आयुक्त बनाया है बल्कि स्पेशल सिकरेट्री टू सीएम से लेकर उनका डायरेक्टर माईनिंग और एमडी माईनिंग कारपोरेशन भी यथावत रहेगा। एन बैजेंद्र कुमार को छोड़ किसी भी जनसंपर्क आयुक्त का इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं रहा।

रायपुर। कई दिनों की अटकलबाजियों और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने रजत बंसल को नया जनसंपर्क आयुक्त अपाइंट कर दिया। इसके साथ ही वर्तमान जनसंपर्क आयुक्त डॉ0 रवि मित्तल को पीएमओ के लिए आज कार्यमुक्त कर दिया।

रजत बंसल 2012 बैच के आईएएस हैं। छत्तीसगढ़ कैडर में वे बैचवाइज सबसे सीनियर हैं। रजत संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी होंगे। सीपीआर और संवाद के सीईओ के साथ उन्हें स्पेशल सिकरेट्री टू सीएम सचिवालय भी बनाया गया है। इसके अलावा उनके पास डायरेक्टर माईनिंग और एमडी माईनिंग कारपोरेशन का भीप अतिरिक्त दायित्व होगा।

सरकार ने जताया भरोसा

नए जनसंपर्क आयुक्त के लिए सरकार के समक्ष तीन-चार नाम थे। मगर आखिरकार रजत बंसल के नाम पर न केवल मुहर लगाया गया बल्कि उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें सीएम सचिवालय में पोस्टिंग दी गई। इसके अलावा उनके पास डायरेक्टर माईनिंग और एमडी माईनिंग कारपोरेशन का भी प्रभार रहेगा। छत्तीसगढ़ में बैजेंद्र कुमार को छोड़ दें तो किसी जनसंपर्क आयुक्त के पास इतना चार्ज नहीं रहा। इस तरह कह सकते हैं कि सरकार ने रजत बंसल पर भरोसा जताया है।

जनसंपर्क आयुक्त के लिए वैसे तो पब्लिक डोमेन से लेकर ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में कई नाम चल रहे थे। मगर रजत बंसल को सबसे उपयुक्त समझा गया। रजत बंसल की खासियत यह है कि वे काफी मिलनसार तो हैं ही, रिजल्ट ओरियेंटेड काम करते हैं। माईनिंग में उन्होंने कम समय में काफी काम किया। इसके अलावे उनकी सबसे बड़ी खासियत लो प्रोफाइल में रहना है। वे पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के दामाद हैं। राजीव कुमार जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, तब भी वे लाइमलाइट से दूर लो प्रोफाइल में बने रहे। रजत काफी विनम्र स्वभाव के आईएएस माने जाते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के भी वे प्रिय हैं। सारी खूबियों को देखते हुए रजत को सरकार की छवि चमकाने वाले विभाग का दायित्व सौंपा गया है।

3 महीने में 300 करोड़ का राजस्व

रजत बंसल मुख्यमंत्री से लेकर हाई अथॉरिटी की नजर में इसलिए आए कि उन्होंने माईनिंग में आते ही इतने बड़े-बड़े काम किए, वैसा आज तक नहीं हुआ। माईनिंग में उनके द्वारा किए गए रिफार्म की वजह से सरकार को पिछले तीन महीने में 300 करोड़ का राजस्व बढ़ गया। माईनिंग में वे ऐसा काम कर रहे कि दलालों और माफियाओं की दाल नहीं गल पाएगी। वे ड्रोन सिस्टम से खनन एरिया की निगरानी कराने जा रहे हैं। ड्रोन का कंट्रोल रायपुर में रहेगा। रायपुर में बैठेक-बैठे पता चल जाएगा कि कहां से कितनी रेत या खनिज को पार किया जा रहा या माइनिंग कंपनियां वास्तविक जगह पर खनन कर रही या रकबा बढ़ाकर माईनिंग कर ले रही।

जानिए रजत बंसल के बारे में

रजत बंसल छत्तीसगढ़ कैडर के 2012 बैच के आईएएस अफसर हैं। वे हरियाणा के रहने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी की है। अपने पहले प्रयास में आईपीएस बने फिर दूसरे प्रयास में आईएएस।

छत्तीसगढ़ कैडर के 2012 बैच के आईएएस रजत बंसल हरियाणा के रहने वाले है। उनके पिता भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे। वे यूपी कैडर के आईएफएस अधिकारी रहे इसलिए रजत की शुरूआती स्कूली शिक्षा यूपी में हुई। रजत बंसल का जन्म 25 जुलाई 1988 को हुआ है। उनकी स्कूली शिक्षा लॉ मार्टिनियर स्कूल लखनऊ व डीपीएस स्कूल आरके पुरम दिल्ली से हुई है। दसवीं में रजत बंसल ने स्कूल में टॉप किया था। बीट्स प्लानी से कंप्यूटर साइंस ब्रांच से इंजीनियरिंग किया। पढ़ाई के दौरान फ्रांस में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुए। जिसमे उन्हें स्कॉलरशिप मिली।

यूपीएससी में सलेक्शन

2009 से अप्रेल 2011 तक इंफोसिस कंपनी पुणे में जूनियर रिसर्च एसोसिएट के तौर पर कार्यरत रहें। इस दौरान यूपीएससी की तैयारी भी करते रहे। हफ्ते में दो दिन नौकरी करते हुए रजत बंसल कोचिंग करते थे। पहले प्रयास में 168 रैंक लाकर यूपीएससी क्रैक करते हुए उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ। रजत बंसल को पश्चिम बंगाल कैडर मिला। 9 माह तक रजत बंसल ने आईपीएस की ट्रेनिंग की। दूसरे प्रयास में रजत बंसल का रैंक 85 वां आया और वे आईएएस के लिए चुने गए।

प्रोफेशनल कैरियर

रजत बंसल ने 3 सितंबर 2012 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की। रजत बंसल की फील्ड ट्रेनिंग के लिए पहली पोस्टिंग सहायक कलेक्टर के रूप में रायगढ़ जिले में मिली। अगस्त 2014 में राजनांदगांव के एसडीएम बने। राजनांदगांव के सीईओ जिला पंचायत बने। फिर सूरजपुर जिले में जिला पंचायत सीईओ बने। रायपुर नगर निगम के कमिश्नर रहें।

रजत बंसल धमतरी, बस्तर व बलौदाबाजार जिलों के कलेक्टर रहें। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के आयुक्त रहें। वर्तमान में वे डायरेक्टर माईनिंग, एमडी माईनिंग कारपोरेशन और स्पेशल सिकरेट्री गुड गवर्नेंस हैं। मगर अब उन्हें जनसंपर्क आयुक्त के साथ विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बनाया गया है। माईनिंग के उनके दोनों प्रभार यथावत रहेंगे। सिर्फ स्पेशल सिकरेट्री गुड गवर्नेंस हटेगा।

पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी में हुए बड़े बदलावों

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कई तरह के बदलाव दिख रहे हैं. इस संदर्भ में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने मीडिया से चर्चा की है. कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी में हुए बड़े बदलावों, पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार और भविष्य की रणनीति पर उन्होंने मंथन किया है. रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित 'हमर पहुना' कार्यक्रम में यह चर्चा हुई.

रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने बताया कि कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी में तुरंत निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत हुई है.थाना स्तर पर जवाबदेही बढ़ी है, ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित किया गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती और निगरानी को तकनीक से जोड़ा गया है.

ट्रैफिक, कानून व्यवस्था और जनता से संवाद पर फोकस

डॉ. संजीव शुक्ला ने मीडिया को बताया कि राजधानी में ट्रैफिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशे के खिलाफ अभियान को प्राथमिकता दी गई है. कमिश्नरी व्यवस्था के तहत विभिन्न जोन में बेहतर समन्वय से कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले से अधिक प्रभावी हुई है.साथ ही जनता से सीधा संवाद, जनचौपाल और शिकायतों के तुरंत हल से पुलिस की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ा है.

टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर

आने वाले समय की रणनीति साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि स्मार्ट सर्विलांस, AI आधारित मॉनिटरिंग, साइबर क्राइम यूनिट की मजबूती और ट्रैफिक ऑटोमेशन पर तेजी से काम किया जा रहा है.राजधानी को और सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक संसाधनों, CCTV नेटवर्क विस्तार और पुलिस-जन भागीदारी को बढ़ाया जाएगा।

कार्यक्रम के अंत में प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर का आभार व्यक्त किया. संवाद के दौरान पत्रकारों ने भी कमिश्नरी व्यवस्था से जुड़े कई सवाल उठाए, जिनका डॉ. संजीव शुक्ला ने विस्तार से जवाब दिया.

आदतन अपराधियों से भरवाया जा रहा बॉन्ड

रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अपराध पर लगाम के लिए नई पहल शुरू की गई है. पुलिस आदतन अपराधियों से बॉन्ड भरवा रही है, ताकि वे दोबारा अपराध न करें. अब तक 1000 से ज्यादा अपराधियों से बॉन्ड लिया जा चुका है.

रायपुर में बढ़ते अपराध को काबू करने के लिए पुलिस ने एक नई सख्त पहल शुरू की है. पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब आदतन अपराधियों से बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं, ताकि वे भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहें. पुलिस का दावा है कि इस कदम से अपराध के ग्राफ में कमी आएगी, लेकिन धरना-प्रदर्शन करने वालों से भी बॉन्ड लेने को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.

ढाई महीने पहले रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी. इसके बाद पुलिस ने अपराध पर रोक लगाने के लिए अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई शुरू की. इसी कड़ी में अब पुलिस ने आदतन अपराधियों पर दबाव बनाने के लिए बॉन्ड भरवाने की प्रक्रिया अपनाई है.

पुलिस के मुताबिक, अपराधी दो तरह के होते हैं. कुछ लोग आवेश में आकर अपराध कर बैठते हैं, जबकि कुछ आदतन अपराधी बार-बार कानून तोड़ते हैं. ऐसे आदतन अपराधियों से शपथ पत्र के साथ बॉन्ड भरवाया जा रहा है, जिसमें वे यह लिखकर देते हैं कि आगे किसी अपराध में शामिल नहीं होंगे. यदि वे दोबारा अपराध करते हैं, तो उनका बॉन्ड जब्त कर लिया जाएगा.

1000 से ज्यादा अपराधियों से भरवाया बॉन्ड- पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी तक रायपुर में एक हजार से ज्यादा आदतन अपराधियों से बॉन्ड भरवाए जा चुके हैं. पुलिस का मानना है कि आर्थिक दबाव और कानूनी कार्रवाई के डर से ऐसे लोग अपराध से दूर रहेंगे. रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला का कहना है कि बॉन्ड की प्रक्रिया का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि अपराध को रोकना है.

आईपीएस डॉ. संतोष सिंह की किताब की राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा

एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने की सराहना

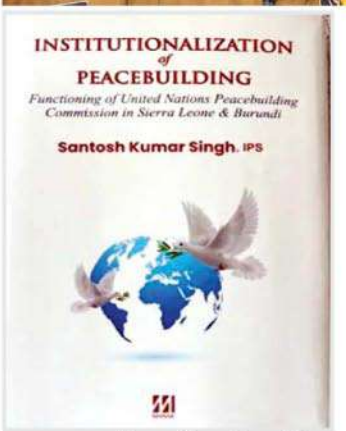

रायगढ़। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में पदस्थ उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह के शैक्षणिक शोध कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। डॉ. सिंह द्वारा लिखित पुस्तक 'इन्सटीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पीस-बिल्डिंग-फंक्शनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पीस-बिल्डिंग कमीशन इन सिएरा लियोन एंड बुरुंडी' की प्रशंसा देश के दो सबसे ताकतवर और वरिष्ठ अधिकारियों ने की है।

पीएमओ से जारी पत्रों में हुई तारीफ

प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली से जारी दो अलग-अलग आधिकारिक पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास ने डॉ. सिंह के कार्यों को सराहा है। अजीत डोभाल (NSA) ने डॉ. सिंह की पुस्तक को 'अत्यधिक शोधपूर्ण और सामयिक' बताया। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि यह संयुक्त राष्ट्र की पीस बिल्डिंग कमीशन की कार्यप्रणाली को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बदलते वैश्विक परिदृश्य और संघर्षों के बीच शांति स्थापना के प्रयासों को समझने के लिए इस तरह के अध्ययन की आवश्यकता है।

वहीं, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास ने भी डॉ. सिंह को पत्र लिखकर इस महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसे तैयार करने में किए गए समर्पित प्रयास सराहनीय हैं। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉ. संतोष कुमार सिंह को उनके अकादमिक एवं पेशेवर जीवन में निरंतर सफलता की शुभकामनाएं भी दी हैं।

आईपीएस संतोष सिंह बने सीआईएसएफ में डीआईजी

2011 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस संतोष सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में डीआईजी के पद पर प्रतिनियुक्ति मिली हैं। संतोष सिंह पुलिस मुख्यालय में डीआईजी सीसीटीएनएस, एससीआरबी के पद पर पदस्थ हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आईपीएस संतोष सिंह की डेपुटेशन को मंजूरी देते हुए आदेश जारी कर दिया हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में आईपीएस सिंह को तत्काल नई जिम्मेदारी पर ज्वाइन करने के लिए रिलीव करने कहा गया हैं।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF केंद्र की सुरक्षा एजेंसी है जो केंद्र के औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करती है। एयरपोर्ट,परमाणु संयंत्र संस्थानों, सरकारी इमारतों और देश की संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन पर है। हाल ही में बंदरगाहों की सुरक्षा का भी जिम्मा सौंपा गया है।

2011 बैच के हैं आईपीएस संतोष सिंह

डॉ संतोष सिंह, आईपीएस 2011 बैच, गृह जिला- गाजीपुर, यूपी। जनवरी 2025 में पुलिस उप-महानिरीक्षक (डीआइजी) के पद पर मिली पदोन्नति। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू), वाराणसी से राजनीति-शास्त्र में एमए की मास्टर डिग्री हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) नई दिल्ली से एम.फिल व दुर्ग विश्वविद्यालय से संयुक्त राष्ट्र के शांति-निर्माण कार्यों पर पीएचडी की डिग्री मिली।

रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, कोरिया, रायगढ़, महासमुंद, नारायणपुर व कोंडागांव जिलों में एसपी, एसएसपी के रूप में पदस्थ रहे।

जनजातीय जड़ों से अंतर्राष्ट्रीय फलक तक

छत्तीसगढ़ की स्टार फुटबॉलर किरण पिस्दा के संघर्ष की कहानी

जब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के सेमीफाइनल में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट के दौरान किरण पिस्दा ने गोलकीपिंग के दस्ताने पहने, तब वह अपने अब तक के अनुभवों पर भरोसा कर रही थीं। उन अनुभवों पर, जिन्होंने चुनौतियों और निराशाओं के बीच उन्हें और अधिक मजबूत बनाया।

24 साल की उम्र में किरण अपने खेल कौशल के शिखर पर नजर आती हैं। वह यूरोप में लीग फुटबॉल खेल चुकी हैं और अब बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने की दहलीज पर हैं।

हालांकि, उनका यह सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा, भले ही उन्हें स्कूल और परिवार से शुरुआती समर्थन मिला। उनके भाई गिरीश पिस्दा, जो खुद राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनके लिए प्रेरणा बने।

किरण ने साई मीडिया से कहा, मुझे स्कूल में काफी सपोर्ट मिला। वहीं से मुझे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के मौके मिले और हर चयन के साथ मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। इसके बाद किरण शारीरिक शिक्षा में डिग्री हासिल करने के लिए रायपुर आईं। छत्तीसगढ़ महिला लीग के दौरान उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और उन्हें राष्ट्रीय शिविर के लिए बुलावा मिला।

किरण बताती हैं, उस समय मैं शारीरिक रूप से उतनी फिट नहीं थी और मेरा मानसिक स्तर भी सीनियर खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं था। यही कारण रहा कि उस राष्ट्रीय शिविर में उन्हें भारतीय टीम के लिए चयन नहीं मिला। वह कहती हैं, मुझे एहसास हुआ कि वहां जो अनुभव मिला है, उस पर मुझे काम करना होगा।

इसके बाद उनके जीवन में आत्म-सुधार का एक कठिन दौर शुरू हुआ। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, मैचों का विश्लेषण करना शुरू किया और अपनी पोज़िशनल समझ को बेहतर बनाया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनकी मानसिकता में आया।

वह कहती हैं, मैंने खुद से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नकारात्मक नहीं सोचूंगी। अगर आप नकारात्मक हो जाते हैं, तो उसका सीधा असर आपके प्रदर्शन पर पड़ता है। इस बदलाव में उनके मेंटर और कोच योगेश कुमार जांगड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किरन ने कहा,जब भी मुझे लगता है कि मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हूं या मन खराब होता है, तो मैं उनसे बात करती हूं। वह हमेशा मुझे सकारात्मक रहने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

किरण की मेहनत का असर धीरे-धीरे दिखने लगा। घरेलू स्तर पर उनके प्रदर्शन ने केरल ब्लास्टर्स जैसे क्लबों के दरवाजे खोले, जहां उन्होंने खुद को और निखारा। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बहुमुखी प्रतिभा बन गई। वह कहती हैं, मैंने स्ट्राइकर के रूप में शुरुआत की, फिर मिडफील्ड में खेली और अब राष्ट्रीय टीम के लिए फुल-बैक के रूप में खेलती हूं। एक फुटबॉलर के रूप में आपको अपनी टीम के लिए कई पोज़िशन पर खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

किरण कई बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वह 2022 के सैफ चैंपियनशिप स्क्वाड का हिस्सा रही हैं और ज़ोएशियन महिला लीग में डिनामो ज़ाग्रेब के लिए भी खेल चुकी हैं। फिर भी, इस मुकाम पर भी असफलताएं उनके सफर का हिस्सा रही हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एएफसी महिला एशियन कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए चयन न होना उनके लिए एक और परीक्षा थी।

किरण कहती हैं,बड़े टूर्नामेंट के लिए चयन न होना दुख देता है। हर खिलाड़ी इसे महसूस करता है। लेकिन अब मैं इसे अलग नजरिए से देखती हूं। इसे मैं और मेहनत करने और मजबूत वापसी करने की प्रेरणा मानती हूं। दबाव को संभालना उनकी पहचान बन चुका है। चाहे टीम में जगह के लिए प्रतिस्पर्धा हो या अहम मैचों में प्रदर्शन, उन्होंने खुद को संयमित रखना सीख लिया है। वह कहती हैं, ऊंचे स्तर पर खेलते समय दबाव हमेशा रहता है। आपको उसे संभालना सीखना पड़ता है।

किरण टीम के प्रदर्शन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानती हैं। उन्होंने कहा, अगर टीम अच्छा कर रही होती है, तो हर खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरा होता है। लेकिन जब टीम हार रही होती है, तो व्यक्तिगत प्रदर्शन भी प्रभावित होता है।जनजातीय पृष्ठभूमि से आने वाली किरण दूर-दराज के इलाकों के खिलाड़ियों की चुनौतियों को अच्छी तरह समझती हैं। उनका मानना है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जैसे मंच इस अंतर को पाटने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

वह कहती हैं, जनजातीय इलाकों में बहुत प्रतिभा है, लेकिन खिलाड़ियों को हमेशा मौके नहीं मिलते। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ने उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है। इससे उन्हें आत्मविश्वास और राज्य तथा देश के लिए खेलने का सपना देखने की प्रेरणा मिलती है। जहां तक किरण का सवाल है, उनका फोकस फिलहाल इंडियन वुमेंस लीग जैसी घरेलू प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने और राष्ट्रीय टीम में नियमित जगह बनाने पर है। लेकिन उनका लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है।

वह कहती हैं, मैं लगातार खुद को बेहतर बनाना चाहती हूं, नियमित प्रदर्शन करना चाहती हूं और बड़े टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूं। अगर आपका चयन नहीं होता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं—इसका मतलब है कि आपको और मेहनत करनी होगी।

आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं ग्रामीण महिलाएं

गृह उद्योग और हस्तशिल्प से संवर रहा भविष्य

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के प्रभावी क्रियान्वयन से रायगढ़ जिले की ग्रामीण महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। यह योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, कौशल और सामाजिक पहचान भी प्रदान कर रही है।

रायगढ़ जिले के ग्राम बड़ेभंडार की निवासी श्रीमती मथुरा कुर्रे इसकी उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के पश्चात उन्हें रिवॉल्विंग फंड एवं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। इस सहयोग से उन्होंने घर पर ही अचार, पापड़, बड़ी एवं मसाला निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। आज वे अपने उत्पादों का बाजार में विक्रय कर नियमित आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और वे आत्मनिर्भर बन सकी हैं।

इसी क्रम में ग्राम रूमकेरा, तहसील घरघोड़ा की श्रीमती जमुना सिदार की कहानी भी प्रेरणादायक है। पूर्व में वे एक गृहिणी थीं, किन्तु बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्होंने बांस शिल्प का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण उपरांत उन्होंने टोकरी, सूपा एवं अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण प्रारंभ किया। उन्हें विभिन्न मेलों, विशेषकर 'सरस मेला' में अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे वे अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि कौशल विकास, उद्यमिता और आत्मगौरव का अवसर भी प्रदान कर रहा है। जिले में अनेक महिलाएं इस योजना से जुड़कर स्वरोजगार के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं।

शासन के मंशानुरूप जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं से जोड़कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, जिससे वे न केवल अपने परिवार की आय में वृद्धि कर रही हैं, बल्कि समाज में एक सशक्त भूमिका भी निभा रही हैं।

बिहान योजना आज जिले में महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बनी है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

नक्सलवाद का अंधेरा छोड़ शर्मिला ने थामी स्वावलंबन की सुई

बस्तर संभाग के नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद अब हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बीजापुर की शर्मिला पोयामी बनकर उभरी हैं, जिन्होंने कभी हाथों में बंदूक थामी थी, लेकिन आज वे लाइवलीहुड कॉलेज में सुई-धागे से अपने और अपने परिवार के भविष्य के सपने बुन रही हैं।

बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक की रहने वाली 19 वर्षीय शर्मिला कभी भैरमगढ़ एरिया कमेटी की सक्रिय सदस्य थीं। गुरिल्ला युद्ध और हथियारों का प्रशिक्षण लेने वाली शर्मिला को जल्द ही अहसास हो गया कि प्रगति का मार्ग बंदूक से नहीं, बल्कि शांति और शिक्षा से निकलता है। इसी संकल्प के साथ उन्होंने 07 फरवरी 2026 को आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया।

राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत शर्मिला को दंतेवाड़ा के लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया। बीते 45 दिनों से वे यहाँ सिलाई का गहन प्रशिक्षण ले रही हैं। अब वे आधुनिक परिधान जैसे सूट और ब्लाउज सिलने की बारीकियां सीख रही हैं। प्रशिक्षण के बाद उनका लक्ष्य अपने गाँव लौटकर सिलाई केंद्र खोलना और अपनी 4 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर आधुनिक खेती (टमाटर, मूली व भाजियाँ) कर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना है। शर्मिला ने बताया कि मुख्यधारा में लौटने के बाद उन्हें पहली बार शासन की ओर से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं।

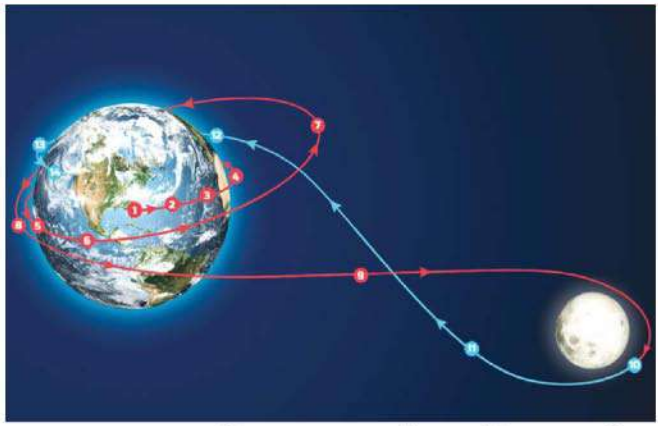

मनुष्य के सपनों की नयी उड़ान है आर्टेमिस 2

आर्टेमिस 2 उस लंबे सफर का अगला पड़ाव है, जिसकी शुरुआत लगभग 50 वर्ष पहले हुई थी. वर्ष 1960-70 के दशक में अपोलो प्रोग्राम ने दुनिया को चौंका दिया था. खासकर अपोलो 11 ने, जब पहली बार मनुष्य ने चांद पर कदम रखा था.

एक अप्रैल, 2026 को मानवता ने एक बार फिर इतिहास रचने की दिशा में तब महत्वपूर्ण कदम उठाया, जब आर्टेमिस 2 का अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित जॉन एफ केनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण हुआ. यह सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के सपनों, हिम्मत और भविष्य की नयी उम्मीदों का प्रतीक है. नासा द्वारा संचालित यह मिशन इस बात का प्रमाण है कि मानवीय जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती. यह मिशन वर्तमान पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि हम सिर्फ धरती तक सीमित नहीं हैं, हमारा भविष्य अंतरिक्ष की समझ के साथ आगे बढ़ रहा है.

आर्टेमिस 2 उस लंबे सफर का अगला पड़ाव है, जिसकी शुरुआत लगभग 50 वर्ष पहले हुई थी. वर्ष 1960-70 के दशक में अपोलो प्रोग्राम ने दुनिया को चौंका दिया था. खासकर अपोलो 11 ने, जब पहली बार मनुष्य ने चांद पर कदम रखा था. वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद मनुष्य का चांद पर जाना स्थगित रहा. इसके बाद कई वर्षों तक अंतरिक्ष मिशन सिर्फ पृथ्वी की नजदीकी कक्षा तक सीमित रहे. लेकिन मनुष्य जिज्ञासु होता है. इसी मानवीय जिज्ञासा के कारण आर्टेमिस प्रोग्राम की शुरुआत हुई. इस प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ चांद पर जाना नहीं, वहां लंबे समय तक रहना, रिसर्च करना और आगे मंगल ग्रह तक पहुंचने का रास्ता तैयार करना था. इस सफर की पहली सफलता थी आर्टेमिस 1, जो 2022 में मानवरहित चांद पर गया और सुरक्षित वापस लौटा.

इस मिशन ने साबित किया कि रॉकेट सिस्टम तकनीकी रूप से मनुष्य को चांद पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है. अब आर्टेमिस 2 उसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए चार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 'इंटीग्रिटी' नामक मिशन पर करीब 10 दिनों की यात्रा पर निकला है. यह मिशन चांद की कक्षा में जाकर वापस पृथ्वी पर लौटेगा. पिछले 50 वर्षों में यह पहली बार है, जब मनुष्य पृथ्वी की नजदीकी कक्षा से बाहर गया है. इस मिशन में इस्तेमाल की गयी अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली (एसएलएस) को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है. एक अनुमान के अनुसार, यह रॉकेट एक बार में लगभग 27 लाख किलोग्राम तक का यांत्रिक बल उत्पन्न कर सकता है.

आर्टेमिस 2 में इस्तेमाल होने वाला ओरियन अंतरिक्ष यान आधुनिक तकनीक का शानदार उदाहरण है. इसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन, पानी देता है और तापमान नियंत्रण में मदद करता है. यह यान लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है. यदि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो यह मिशन अपोलो 13 मिशन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है, जिसमें मनुष्य ने पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तय की थी. आर्टेमिस 2 की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं है कि यह चांद पर पहुंच रहा है, बल्कि यह है कि यह मनुष्य को सुरक्षित रूप से गहरे अंतरिक्ष में ले जाकर वापस ला रहा है. यह मिशन भविष्य के बड़े मिशनों के लिए एक परीक्षण है. इसके जरिये यह देखा जाना है कि मनुष्य लंबे समय तक अंतरिक्ष में कैसे रह सकता है, वहां के रेडिएशन का शरीर पर क्या असर होता है, और तकनीक कितनी भरोसेमंद है.

इसका मकसद है चांद को और अच्छे से समझना, विज्ञान और आर्थिकी के लिए नये मौके बनाना तथा मंगल पर मनुष्य को भेजने की तैयारी करना. आगे की योजनाएं और भी रोमांचक हैं. अगला मिशन आर्टेमिस 3 होगा, जिसमें मनुष्य दोबारा चांद की सतह पर कदम रखेगा. इसके बाद नासा चांद पर एक स्थायी बेस (लूनर बेस) बनाने की योजना बना रहा है. इस बेस का इस्तेमाल वैज्ञानिक शोध और नये संसाधनों की खोज के लिए किया जावेगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर मौजूद बर्फ को पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल में बदला जा सकता है. इससे भविष्य के मिशन और भी आसान हो जायेंगे. आर्टेमिस 2 केवल एक अंतरिक्ष मिशन नहीं है, यह मानवता के भविष्य की नींव है. इससे नयी तकनीकों का विकास होगा, जो धरती पर भी काम आयेंगी. जैसे, बेहतर मेडिकल उपकरण, संचार तकनीक और ऊर्जा के नये स्रोत.

भारत के लिए भी यह मिशन बहुत महत्व रखता है. इसरो ने बीते कुछ वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया, जिन्होंने चांद पर सफल लैंडिंग की है, वह भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, जो अब तक सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता था. इसके अतिरिक्त, मंगलयान ने साबित किया कि भारत कम लागत में भी बड़े अंतरिक्ष मिशन कर सकता है. आर्टेमिस प्रोग्राम भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नये अवसर खोलता है. आने वाले समय में भारत भी इन मिशनों का हिस्सा बन सकता है, जिससे देश की तकनीकी क्षमता और बढ़ेगी. भारत का अपना मानव अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. आज जब आर्टेमिस 2 चांद के पास अपनी यात्रा कर रहा है, तो यह केवल चार अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं ले जा रहा, बल्कि पूरी मानवता के सपनों को नयी उड़ान के लिए तैयार कर रहा है. अंत में, आर्टेमिस 2 हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ पृथ्वी के निवासी नहीं हैं, हम अन्वेषक हैं.

'रील सच, रियल भ्रम'

घटता धैर्य और सिमटता वक्त, नए दौर में बदलती जिंदगी

सच यह है कि व्यस्त दिखती यह आबादी अपने मोबाइल में और उसके भीतर सोशल मीडिया पर फैले रील के जंजाल में खोई लगती है। उठते-बैठते, चलते-फिरते, यहां तक कि जरूरी विमर्श और बैठकों में भी आदमी बेमतलब ही स्मार्टफोन की स्क्रीन में गुम दिखता है, रील में डूबता-उतराता रहता है।

मौजूदा दौर में अगर लोगों की व्यस्तता पर गौर किया जाए, तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर आबादी काम के बोझ से दब चुकी है और हर वक्त किसी बहुत जरूरी काम को पूरा करने में लगी हुई है। सच यह है कि व्यस्त दिखती यह आबादी अपने मोबाइल में और उसके भीतर सोशल मीडिया पर फैले रील के जंजाल में खोई लगती है। उठते-बैठते, चलते-फिरते, यहां तक कि जरूरी विमर्श और बैठकों में भी आदमी बेमतलब ही स्मार्टफोन की स्क्रीन में गुम दिखता है, रील में डूबता-उतराता रहता है।

हालत यह है कि रील को लेकर ज्यादा संवेदनशील लोग दाह-संस्कार जैसे अवसरों पर भी रील पर अंगुलियां चलाते रहते हैं। मानो घटनाओं का रील में होना जरूरी हो गया है। व्यक्ति की छोटी से छोटी निजी घटनाएं भी सोशल मीडिया पर डाल दी जाती हैं। घर के दरवाजे से बाहर निकलते हुए फिसल जाने की निजी घटनाओं के भी वीडियो बनाए जाते हैं। दरअसल, रील बनाना प्रसिद्धि बटोर लेने का साधन बन गया है। बल्कि इसके लिए घटनाएं बनाई जा रही हैं। फिल्मों की कतरनें डाली जा रही हैं।

सोशल मीडिया के जरिए दुनिया पर छा जाने का चलन नया नहीं है। रुपहले पर्दे के कलाकार रील की बदौलत दुनिया को आकर्षित करते रहे हैं। एक जमाना था, जब सिनेमा ही मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। फिल्म कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा उसकी रील की लंबाई से लगाया जाता था। दर्शक सिनेमाघरों में टिकट खरीदते हुए पूछते थे कि यह फिल्म कितनी रील की है। जवाब में अगर सोलह रील सुनाई देता, तो लोग खुश हो जाते। अपने जमाने की सुपर हिट फिल्म 'शोले' तेईस रील की थी और उसकी कुल अवधि दो सौ चार मिनट थी। दर्शक तीन घंटे चौबीस मिनट सिनेमाघरों में सांस साधे बैठा रहता था।

हर इंसान के पास समय की कमी का रोना रो रहा है

अब हर व्यक्ति समय की भारी कमी बताता दिखता है। इसलिए एक से डेढ़ घंटे की फिल्में चलन में आ गई हैं। समय के साथ धैर्य भी घटा है। वह धैर्य मात्र तीस सेकंड की रील में सिमटता प्रतीत हो रहा है। एक रील समाप्त हुई नहीं कि लोग अगली रील पर बढ़ जाते हैं। अब हालत यह है कि उकसाने वाली रील का एक नया शगल शुरू हो गया है। इनके लिए निजता को भुनाया जा रहा है। एक ओर ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने वालों की भरमार है और दूसरी ओर इनमें खोए लोगों की भी भीड़ है, जो निजी बेचैनी में चैन तलाशने का यत्न संजोती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आने से रील की लोकप्रियता में भारी इजाफा हुआ है। स्थिर छाया चित्रों का रील में समावेशीकरण चलन में आ गया है। लेखक और रचनाकार अपनी रचनाओं की कतरनें और छाया चित्र ऐसे छोटे वीडियो में डालते हैं, ताकि रील दर रील सरकाने की दौड़ में स्थिर छाया चित्रों को एक झलक का स्थान मिल सके। स्थिर छाया चित्रों के पीछे आवाजें डालकर आकर्षक और सुनने लायक बनाया जाता है।

कई बार ऐसे संक्षिप्त वीडियो के पार्श्व की आवाजें भौंडी और चिढ़ पैदा करने वाली होती हैं। मगर ऐसा लगता है कि लोग इसे लेकर एक प्रकार की दुविधा में रहते हैं या फिर सहज हो रहे हैं। मसलन, जिस व्यक्ति को पड़ोस की रसोई से बर्तनों की खटपट की आवाज परेशान कर रही हो सकती है, वह सो नहीं पाता होगा, वही मोबाइल में चल रही रील की पृष्ठभूमि में अजीब-सी हंसी और ठहाकों तथा अन्य आवाजों को लेकर सहज रह सकता है। जबकि यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भले ही ऐसी रीलें लोगों के लिए मनोरंजन के साधन हैं, पर आसपास के लोग इनसे परेशान रहते हैं।

इस प्रवृत्ति के बढ़ते जाने की लत अब विचित्र दिखने लगी है। इस लत के जुनून में डूबा कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के दौरान अगर बच जाता है, तो वह वीडियो बनाने में मशगूल दिख सकता है। बात यहां तक जा पहुंची है कि घायल अवस्था में भी कुछ लोग ऐसे संक्षिप्त वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते हैं और 'लाइक' और 'कमेंट' की बदौलत अपने साथ हुई दुर्घटना पर सहानुभूति जुटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ लोग कराहते दिख सकते हैं और अपने कष्ट और मुसीबत को लेकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं।

इसके अलावा, आए दिन रील बनाने और देखने वाले लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। वहीं एआइ के विस्तार के साथ लोग अब दुनिया की तबाही के रील भी बनाने लगे हैं। एआइ की मदद से आकाश से गिरती विशाल चट्टानें, चट्टानी ओलों की वर्षा से टूटते घर, तबाह होती सड़कें और तूफानों के भय से भागते लोग रील में दिखाए जा रहे हैं। तबाही के ऐसे वीडियो के बीच अजब-गजब-सी रीलों का दौर भी चल पड़ा है। आसमान से नोटों या जानवरों की वर्षा होती दिखाई देती है। ऐसे वीडियो से असल और नकल की पहचान गुम हो रही है।

बचपन की बेफिक्री बनाम बड़ों की चिंता

जब भी हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं कि जीवन के सबसे खूबसूरत पल बचपन के होते हैं। कोई चिंता नहीं होती। जब जी चाहा खाया, जब जी चाहा सोए और अपने मन की चीज चाहने की जिद की। सामान्य परिस्थितियों में वह चाहत अक्सर पूरी भी हो जाती है। पर जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा अल्हड़पन धीरे-धीरे गायब होने लगता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी इच्छाएं मात्र प्राकृतिक आवश्यकताओं तक सीमित होती हैं। इसके बाद धीरे-धीरे उसकी मनोरंजन की आवश्यकता प्रकट होती है, पर यह अनिवार्य नहीं कि उसे किसी खास तरह के खिलौनों की आवश्यकता हो। उसके लिए मिट्टी भी खिलौना हो सकती है। वह जो कुछ अपने आसपास देखता है, उसे ही जिज्ञासावश छूता है, महसूस करता है और अपना मनोरंजन करता है।

बालपन की जो सबसे आकर्षक प्रवृत्ति है बच्चों की बेफिक्री, उनका मस्तानापन। ये बेफिक्री जीवन में हमेशा ही एक बार फिर से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बच्चा बन जाने की इच्छा बनाए रखने के लिए मजबूर कर देती है। शायद इसीलिए सुदर्शन फाकिर ने लिखा है कि 'ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन..!' दरअसल, बचपन ऐसा होता है कि उसे फिर से पाने के लिए एक बार सब कुछ लुटा देने को जी चाहता है।

एक बच्चे की सबसे अद्भुत शक्ति होती है उसके भीतर बसने वाला असीम विश्वास। ऐसा विश्वास जो उसे कभी उदास नहीं होने देता। अगर वह एक पल रोता है, तो दूसरे ही पल फिर हंसकर अपने खेल में लग जाता है। बच्चा या तो हंसता है या रोता है, उदास नहीं होता। उसे मानो कोई चिंता नहीं होती कुछ खोने की। यों भी, वह क्या खोएगा? उसके पास जिस समय जो होता है, उसे ही वह अपना सर्वस्व मान लेता है।

बच्चे पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं

हम कभी ध्यान से किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए देखें, तो पाएंगे कि अगर वह किसी एक खिलौने से खेल रहा है और उसे कोई दूसरा खिलौना मिल जाता है कहीं से, तो वह पहले वाला खिलौना छोड़कर दूसरे से खेलने में लग जाता है। वह यह बिल्कुल नहीं सोचता कि पहले वाले खिलौने को जाकर कहीं छिपा दूं या ताले में बंद कर दूं और उसके बाद दूसरे से खेलूं। वह सहज ही पहले को छोड़ता है और दूसरे से अपनी जिज्ञासा शांत करने में लग जाता है। यानी वह पूरी तरह से वर्तमान में जीता है। न तो वह पहले वाले खिलौने को याद करता है और न ही यह सोचता

एक बच्चे की सबसे अद्भुत शक्ति होती है उसके भीतर बसने वाला असीम विश्वास। ऐसा विश्वास जो उसे कभी उदास नहीं होने देता। अगर वह एक पल रोता है, तो दूसरे ही पल फिर हंसकर अपने खेल में लग जाता है। बच्चा या तो हंसता है या रोता है, उदास नहीं होता।

है कि अब उसे अगला कौन-सा खिलौना मिलने वाला है। जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है, तो सब कुछ छोड़कर रोना शुरू कर देता है। उसके पूरा होते ही रोना भूलकर फिर खेलने लगता है। उसे इस बात का भी दुख नहीं होता कि उसे रोना पड़ा। उसके पास अहंकार नहीं होता, जिसे रोने से या किसी से गुहार लगाने में चोट महसूस हो।

इसके विपरीत, अगर हम अपनी बात करें तो हमारी स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। हम अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा फिक्र करने और उदास रहने में बिता देते हैं। हम या तो अतीत के दुखों में डूबे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। सूरज की रोशनी हम पर उतना प्रकाश नहीं डाल पाती, जितना बीत चुकी रात या आने वाली रात का अंधेरा हमें खुद में डुबोए रखता है। इस चिंता के पीछे वास्तव में हमारा अपना अहंकार होता है, जो हमें सब कुछ का नियंता मानने और अपने नियंत्रण में रखने को प्रेरित करता है। हम न केवल अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर अपने परिवार के लोगों, दोस्तों, पड़ोसियों पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। गौर से विश्लेषण करने पर ये पता चलेगा कि जीवन में रहने वाला अधिकतर तनाव हमें अपनी जीवनरूपी गाड़ी को नियंत्रित करने से नहीं मिलता, बल्कि सबकी गाड़ी के रिमोट कंट्रोल को हासिल करने की कोशिश में लगे रहने से मिलता है।

हम मुट्ठी बांधकर आते हैं इस संसार में और हाथ पसारकर चले जाते हैं। वास्तव में प्रकृति, जीवन की शुरुआत और अंत के बीच एक यात्रा की मंजिल शुरू से ही तय कर देती है। मतलब हम बंधकर आते हैं और हमें मुक्त होकर जाना है।

जीवन वास्तव में बंधन से मुक्ति की यात्रा है। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने माता-पिता पर अपने आप से ज्यादा विश्वास करता है और किसी भी तरह की चिंता से मुक्त रहता है, ठीक वैसे ही मनुष्य को भी अपने विवेक पर विश्वास रखते हुए कर्म करना चाहिए। प्रकृति हमें उन्हीं संसाधनों से विराजती है, जिसकी हम पात्रता रखते हैं। इसलिए हमारे सारे कर्म और हमारी सारी ऊर्जा अपनी पात्रता को बढ़ाने और बनाए रखने में लगनी चाहिए। जिस तरह एक ही माता-पिता की हर संतान अपने जीवन में अलग-अलग मंजिलें तय करती हैं, ठीक उसी तरह हर मनुष्य को प्रकृति ने जीवन दिया है और उसे आकार देने वाले संसाधन भी। सबकी अपनी यात्रा है और जीवन के स्थूल लक्ष्य भी भिन्न हैं। मगर प्रकारांतर से मंजिल सबकी एक है। हमें सब पाना है, खेलना है, सीखना है और उसे किसी और के लिए छोड़ते जाना है। समेटने में अपनी ऊर्जा नहीं गंवानी चाहिए, क्योंकि तब बहुत से खिलौने अछूते रह जाएंगे और हम तमाम नई सीखों से वंचित रह जाएंगे।

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिन नौनिहालों को हम देश का भविष्य मानते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे आज बहुस्तरीय जोखिम के बीच से गुजर रहे हैं। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के अनेक रूप के अलावा बाल तस्करी का संजाल आज इस कदर जटिल होता जा रहा है कि इससे निपटना सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि इस अपराध को काबू में करना और बच्चों को इस खतरे से बचाना सरकार की अनिवार्य जिम्मेदारी और सबसे ऊपर की प्राथमिकता में दर्ज होना चाहिए। मगर हालत यह है कि देश के सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देना पड़ रहा है कि वे बच्चों के खिलाफ इस अपराध को गंभीरता से लें।

जल समस्या केवल 'कितना पानी है' का नहीं, बल्कि 'कैसा पानी है' का भी सवाल

अलका 'सोनी'

हम सभी यह सुनते और जानते हुए बड़े हुए हैं कि जल है तो जीवन है। इसके बावजूद जल का अपव्यय करते हैं। जिस गति से संचय करने की बात की जाती है, उससे कई गुना पानी की बर्बादी होती है। कहीं भी सड़कों पर पानी बहते हुए देखा जा सकता है। यही कारण है कि भारत में जल संकट अब भविष्य की चेतावनी नहीं, वर्तमान की कठोर सच्चाई है। देश के अनेक हिस्सों में भूजल स्तर नीचे जा चुका है, नदियां प्रदूषण से बेहाल हैं। शहरों की जल आपूर्ति व्यवस्था दबाव में है। लोग पानी के लिए घंटों इंतजार में खड़े रहते हैं। जलवायु परिवर्तन ने वर्षा को भी इतना अनिश्चित बना दिया है कि कहीं बाढ़ और कहीं सूखा एक साथ दिखाई देता है। समस्या केवल पानी की कमी की नहीं है, असली संकट यह है कि प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं। जल संचय के लिए बनी नीतियों की धीमी गति और समाज के असंतुलित जल-व्यवहार के बीच आज भारत बुरी तरह उलझता जा रहा है।

भारत में जल संकट इसलिए भी जटिल है, क्योंकि यहां पानी का सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, शहरीकरण, सामाजिक न्याय और शासन-व्यवस्था सबसे जुड़ा है। भूजल पर भारत की निर्भरता बहुत गहरी है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और सरकार द्वारा जारी नवीनतम आकलन के अनुसार, वर्ष 2025 में देश की कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण क्षमता 448.52 बिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई, जबकि वार्षिक निकासी 247.22 बिलियन क्यूबिक मीटर रही। पहली नजर में यह संतुलित लग सकता है, लेकिन सच यह है कि राष्ट्रीय औसत के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन छिपा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां निकासी सुरक्षित सीमा के आसपास या उससे ऊपर है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में संसाधन अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं। यही वजह है कि जल संकट पूरे देश में एक समान नहीं, बल्कि कई रूप में सामने आता है।

इसमें दोराय नहीं कि बांध, नहर, पाइपलाइन और बोरवेल आवश्यक हैं, लेकिन वे अकेले समाधान नहीं हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जल नीति आपूर्ति बढ़ाने से आगे बढ़ कर मांग-प्रबंधन, जल गुणवत्ता, पुनर्भरण, पुनर्चक्रण और स्थानीय जल शासन पर जोर दे। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन की चर्चा महत्त्वपूर्ण हो जाती है। लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा है कि वर्ष 2012 में अद्यतन हुई नीति अब

मौजूदा चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं है। जल संसाधन मंत्रालय के दस्तावेजों में भी यह स्वीकार किया गया है कि कम जल-उपयोग दक्षता, भूजल पर बढ़ता दबाव, जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग और फसल-पद्धति जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल नीति के पुनरीक्षण की जरूरत पड़ी। मिहिर शाह समिति इसी उद्देश्य से गठित की गई थी।

बुनियादी सवाल यह है कि जब संकट इतना स्पष्ट है, तो सुधार की गति इतनी धीमी क्यों है! इसका उत्तर भारत की संघीय संरचना और जल शासन की जटिलता में छिपा है। जल राज्यों का विषय है। केंद्र दिशा दे सकता है, योजनाएं बना सकता है, वित्तीय सहायता दे सकता है, पर वास्तविक क्रियान्वयन राज्यों, स्थानीय निकायों और विभागीय तंत्र के माध्यम से ही होता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी नीयत से बनाई गई नीतियां भी जमीन तक पहुंचते-पहुंचते धीमी पड़ जाती हैं। ऊपर से पानी का प्रश्न राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी है। मुफ्त या सस्ती बिजली, सिंचाई, शहरी जलापूर्ति, उद्योगों की जरूरतें और राज्यों के जल विवाद ये सब मिल कर निर्णय को कठिन बना देते हैं।

कृषि इस बहस के केंद्र में है, क्योंकि भारत में जल उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में होता है। मगर कृषि को दोष देकर समस्या हल नहीं होगी। असल बात यह है कि दशकों से नीतिगत ढांचा ही ऐसे फसल को बढ़ावा देता रहा है जो कई क्षेत्रों में जल-उपलब्धता के अनुकूल नहीं हैं। जहां पानी सीमित है, वहां भी धान या गन्ने जैसी फसलों की खेती जारी रहती है, जिसमें पानी की अधिक जरूरत होती है। इस परिस्थिति में यदि जल संरक्षण की बात की जाए, तो किसानों को विकल्प, तकनीक, सिंचाई, बाजार और मूल्य का आश्वासन भी देना होगा।

समस्या का दूसरा बड़ा कारण जल गुणवत्ता है। कई बार पानी उपलब्ध होता है, पर सुरक्षित नहीं होता। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2025 की वार्षिक भू-जल गुणवत्ता रपट और संसद में सरकार द्वारा साझा जानकारी बताती है कि परीक्षण के लिए एकत्रित 28.3 फीसद नमूनों में नाइट्रेट, फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसी समस्याएं अभी भी गंभीर हैं। दिसंबर 2025 में साझा आंकड़ों के अनुसार 2024 के नमूनों में 3,415 में से 123 नमूनों में आर्सेनिक और 2,537 में से 24 नमूनों में सीसा अनुमेय सीमा से अधिक पाया गया। इसका मतलब साफ है कि भारत की जल समस्या केवल 'कितना पानी है' का प्रश्न नहीं, बल्कि 'कैसा पानी है' का भी प्रश्न है।

शहरी भारत में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। तेजी से बढ़ते शहरों ने अपने स्थानीय जलस्रोतों जैसे तालाबों, झीलों, नालों और जलग्रहण क्षेत्रों को या तो पाट दिया है या उपेक्षित छोड़ दिया है। नतीजा यह हुआ कि शहर अब दूरदराज के स्रोतों, गहरे बोरवेल और टैंकरों पर निर्भर होते गए। यह व्यवस्था महंगी है और असमान भी। धनाढ्य इलाके में लोग पानी खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब बस्तियां अनिश्चित आपूर्ति पर निर्भर रहती हैं। शहरों में सीवर और औद्योगिक अपशिष्ट का पर्याप्त शोधन न होने के कारण सतही जल स्रोत और भूजल दोनों प्रभावित होते हैं। यानी शहर अपने लिए पानी खींचते भी हैं और उसे प्रदूषित भी करते हैं। यह दोहरा दबाव भविष्य की शहरी जल सुरक्षा को और अधिक नाजुक बनाता है। ●

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का पारित होना देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए कहा कि भारतीय सनातन परंपरा में नारी का स्थान सर्वोच्च है। हम भगवान से पहले भगवती की पूजा करते हैं और ऐश्वर्य के लिए माता लक्ष्मी, बुद्धि के लिए सरस्वती और बल के लिए दुर्गा की आराधना की जाती हैं। श्री साय ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयास पहले भी हुए, लेकिन इसे प्रभावी रूप से लागू करने का साहसिक निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और महतारी वंदन योजना जैसी पहलों ने महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हम इस वर्ष को प्रदेश में 'महतारी गौरव वर्ष' के रूप में मना रहे हैं और महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता दी जा रही है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद समाप्त हुआ है और प्रदेश विकास के नए मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को नया संबल मिलेगा। कार्यक्रम में पंचायत से पार्लियामेंट तक निर्णय में नारी—नए भारत की तैयारी के संकल्प को दोहराया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में पहले से ही 14 लाख से अधिक महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जो उनके बढ़ते आत्मविश्वास का प्रमाण है। उन्होंने इस दौरान पुष्प के साथ महिलाओं का अभिनंदन कर बधाई और शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं की इच्छाशक्ति और संकल्प उन्हें बड़े निर्णय लेने में सक्षम बना रहे हैं। महिलाओं को जिम्मेदारी मिले तो वे देश की तस्वीर बदल सकती हैं। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय ने बताया कि यह अधिनियम वर्ष 2029 तक लागू होगा, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

कार्यक्रम में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, पद्मश्री ऊषा बारले, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा, पद्मश्री ऊषा बारले, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नीता डोंगरे सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

हौसला, हुनर और योजनाओं के सहारे महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जानकारी दी और पंजीकरण में मदद की। योजना के तहत मिली 5000 रुपये की सहायता राशि का उपयोग महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदने और अपने काम को विस्तार देने में किया। सही जानकारी और योजनाओं के उपयोग ने इनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी।

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का छोटा सा गांव मनियारी आज एक बड़ी सीख दे रहा है- अगर इरादे मजबूत हों और सही मौके मिल जाएं, तो बदलाव दूर नहीं होता। यहां की पांच महिलाओं ने अपने साहस, आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव में नई सोच की शुरुआत कर दी।इस बदलाव की शुरुआत हुई अनुसूया साहू से। बचपन से सिलाई में माहिर अनुसूया के पास हुनर तो था, लेकिन आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के चलते वह आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उनका सपना कहीं दब सा गया था। मार्च 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को 1000 हजार रूपए की प्रत्येक माह आर्थिक मदद दिए जाने के उद्देश्य से शुरू की गई महतारी वंदन योजना ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई। हर महीने मिलने वाली इस सहायता राशि को खर्च करने के बजाय उन्होंने बचाने का फैसला किया। छह महीने की बचत के बाद उन्होंने सिलाई मशीन ख़रीदी और घर से ही काम शुरू किया। शुरुआत भले ही छोटी थी, कपड़ों की आल्टरिंग और साधारण सिलाई, लेकिन काम की गुणवत्ता ने जल्द ही उन्हें पहचान दिला दी।अनुसूया की कोशिशों ने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। ओमकारेश्वरी साहू ने उनसे सिलाई सीखी और अपना काम शुरू किया। इसके बाद पार्वती, गंगा और हेमिनी भी जुड़ती चली गईं। देखते ही देखते यह पहल एक मजबूत महिला समूह में बदल गई, जहां सहयोग और सीखने की भावना ने इसे आगे बढ़ाया।आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जानकारी दी और पंजीकरण में मदद की। योजना के तहत मिली 5000 रुपये की सहायता राशि का उपयोग महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदने और अपने काम को विस्तार देने में किया। सही जानकारी और योजनाओं के उपयोग ने इनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी। आज ये पांचों महिलाएं मिलकर एक सफल सिलाई केंद्र चला रही हैं। वे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए कपड़े तैयार कर रही हैं। समय पर काम और बेहतर गुणवत्ता के कारण गांव के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी उनकी पहचान बन चुकी है। इस पहल से उनकी आय में वृद्धि हुई है। अब वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दे रही हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब वे परिवार के फैसलों में भी बराबरी से भागीदारी निभा रही हैं। इन महिलाओं की सफलता अब गांव की अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ वे समाज में नई पहचान बना रही हैं।

33% आरक्षण 100% सियासत

बिल गिरा, नैरेटिव उठा, महिला आरक्षण की आड़ में सियासत का मास्टरस्ट्रोक

■ नरेन्द्र पाण्डेय

महिला आरक्षण बिल के संसद में गिर गया . मगर इसके गिरने के पीछे छिपी राजनीतिक रणनीति क्या है? कैसे यह मुद्दा चुनावी नैरेटिव में बदल रहा है और इसका महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा, आइये जाने इस लेख में।

लोकसभा के गलियारों में जो हुआ, वो सिर्फ एक विधेयक का गिरना नहीं था वो एक कहानी की शुरुआत थी—एक ऐसी कहानी, जिसका क्लाइमैक्स अब चुनावी रैलियों में लिखा जाएगा।

'महिला आरक्षण', एक ऐसा मुद्दा, जो दशकों से इंतज़ार में था। लेकिन इस बार, जब वो संसद के दरवाज़े तक पहुंचा— तो अचानक ठिठक गया, गिर गया और फिर उठ खड़ा हुआ— नैरेटिव बनकर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ऊपर से देखेंगे तो तस्वीर साफ है— सरकार बिल लाई, विपक्ष ने रोका, बिल गिर गया। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में उतरेंगे, तो ये पूरा घटनाक्रम किसी सधे हुए राजनीतिक स्क्रिप्ट जैसा लगता है। जैसे मंच पहले से तैयार था, संवाद लिखे जा चुके थे, और किरदारों को पता था कि कब क्या कहना है।

देखिए, जैसे ही बिल गिरने की घोषणा हुई, सत्ता पक्ष की महिला सांसद तख्तियां लेकर बाहर आईं— नारे लगे, कैमरे ऑन हुए और संदेश सीधा जनता तक पहुंचा— 'हमने कोशिश की, विपक्ष ने रोक दिया।' ये विरोध कम और प्रदर्शन ज्यादा लगा। मानो बिल और बैनर एक ही प्रिंटिंग प्रेस से साथ-साथ निकले हों।

इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा का सबसे अहम दृश्य था-गृह मंत्री का लंबा और आक्रामक भाषण। एक घंटा 10 मिनट, हर शब्द एक संदेश, हर वाक्य एक वार। उन्होंने विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए और अपनी सरकार को महिलाओं के हक का एकमात्र प्रहरी बना दिया। यहां तक कि उन्होंने बीच में ही ये संकेत भी दे दिया— कि बिल गिर सकता है लेकिन 'देश की महिलाएं देख रही हैं कि रोड़ा कौन है।' यानी, परिणाम चाहे जो हो, कहानी पहले से तय थी।

अब सवाल ये है— क्या सरकार सच में इस बिल को पास कराना चाहती थी? क्योंकि बिल की संरचना खुद कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल— 50% सीट बढ़ाने का स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं? फिर— इसे जनगणना और परिसीमन से क्यों जोड़ा गया? यानी, आज का हक,भविष्य के भरोसे क्यों टाल दिया गया?

विपक्ष का तर्क यहां कमजोर नहीं था। वो कह रहा था— 'टाइमलाइन दो, जातिगत जनगणना करो, फिर लागू करो।' लेकिन सत्ता पक्ष ने इस तर्क को एक नए रंग में रंग दिया— 'ये महिला विरोध है।' यही वो पल था, जहां राजनीति ने मुद्दे को भावना में बदल दिया।

असल खेल यहीं है। अगर बिल पास हो जाता— तो सरकार को श्रेय मिलता। लेकिन बिल गिर गया— तो सरकार को भावना मिल गई। और राजनीति में, कई बार भावना, श्रेय से ज्यादा ताकतवर होती है।

अब भाजपा के पास एक तैयार नैरेटिव है— एक ऐसा हथियार, जो सीधा दिल पर वार करता है। आने वाले चुनावों में हर रैली में, हर मंच पर यही गूंजेगा— 'हम देना चाहते थे, उन्होंने छीन लिया।' गांव-गांव में पार्टी का कैडर यही कहानी दोहराएगा— कि प्रधानमंत्री आधी आबादी को उनका हक देना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने 'घमंड' में उसे गिरा दिया।

और यहीं पर विपक्ष की मुश्किल शुरू होती है। अब उसे सफाई देनी होगी— कि उसने बिल का विरोध नहीं, उसकी शर्तों का विरोध किया। जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं— 'हमने आरक्षण का नहीं, परिसीमन का विरोध किया।' लेकिन सवाल ये है— क्या ये जटिल तर्क गांव की उस महिला तक पहुंच पाएगा जो सिर्फ इतना समझती है— कि 'मेरा हक रोका गया'? राजनीति की यही क्रूर सच्चाई है। वो तथ्य नहीं बेचती, वो भावनाएं बेचती है। और इस बार— महिला आरक्षण का मुद्दा एक भावनात्मक 'बूस्टर डोज' बन चुका है।

अगर इस पूरी रणनीति का पोस्टमॉर्टम करें, तो एक बात साफ दिखती है— यहां महिलाएं मुद्दा कम, माध्यम ज्यादा थीं। असल लक्ष्य था— विपक्ष को घेरना, उसे रक्षात्मक बनाना और खुद को नैतिक ऊंचाई पर स्थापित करना। लेकिन इस पूरी राजनीतिक बाजीगरी के बीच एक सवाल अब भी खड़ा है— वो आम औरत कहां है? वो, जो पार्टी दफ्तर में सालों से काम कर रही है वो, जो हर रैली में भीड़ जुटाती है वो, जो आज भी टिकट की लाइन में सबसे पीछे खड़ी है।

उसके लिए क्या बदला? सच ये है— संसद में बिल गिरा हो या पास होता, उसकी जिंदगी में फर्क फिलहाल नहीं पड़ने वाला था। क्योंकि असली लड़ाई कानून की नहीं, मानसिकता की है। जब तक राजनीति औरत को 'वोट बैंक' की तरह देखेगी 'पावर शेयर' की तरह नहीं— तब तक ऐसे बिल आते रहेंगे, गिरते रहेंगे और हर बार एक नया नैरेटिव जन्म लेगा। लेकिन इस बार एक फर्क है। औरत अब सिर्फ सुन नहीं रही, वो समझ भी रही है। इसलिए ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। संसद में जो हारा है— वो चुनावी मैदान में जीतेगा या हारेगा— ये तय करेगी वही औरत जो आज तक सिर्फ 'वोट' थी, लेकिन अब 'वॉइस' बनने की तैयारी में है।

क्रेडा विभाग की योजनाओं से दो वर्षों में आमजन के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में क्रेडा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों ने आमजन के जीवन में उल्लेखनीय और सकारात्मक परिवर्तन लाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में सौर ऊर्जा आधारित प्रणालियों के बेहतर उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे विकास की गति को नई दिशा मिली है। विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप अब लोगों को बुनियादी सुविधाएं अधिक सरलता और सहजता से उपलब्ध हो रही हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से जहां एक ओर स्वच्छ पेयजल और सिंचाई व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिना बिजली बिल के निरंतर रोशनी सुनिश्चित हो रही है। इससे न केवल लोगों का दैनिक जीवन अधिक सुविधाजनक हुआ है, बल्कि उनके जीवन स्तर में स्थायी और सकारात्मक सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

114 सोलर ड्यूल पंप से पेयजल और सिंचाई सुविधा सुदृढ़

ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की पहल पर प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

क्रेडा विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में जल जीवन मिशन अंतर्गत जशपुर जिले में 114 सोलर ड्यूल पंप स्थापित किए गए हैं। इनसे पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ सिंचाई के लिए सस्ती एवं सुलभ ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। सोलर पंपों के उपयोग से किसानों की डीजल एवं बिजली पर निर्भरता कम हुई है, जिससे उनकी लागत में कमी आई है और आय में वृद्धि हुई है। पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसान वर्षभर खेती कर पा रहे हैं, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

वहीं घर के समीप जल उपलब्ध होने से महिलाओं को दूर से पानी लाने की परेशानी से राहत मिली है।

80 सोलर हाई मास्ट से रोशन हुए गांव और शहर

जशपुर जिले में सार्वजनिक स्थलों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर हाई मास्ट योजना के तहत ग्रामों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों के प्रमुख चौक-चौराहों पर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों में 80 सोलर हाई मास्ट लगाए जा चुके हैं। इन सौर ऊर्जा आधारित लाइटों से रात्रिकालीन आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हुआ है। साथ ही, दुर्घटनाओं और अपराधों में भी कमी आई है। जहां बिजली आपूर्ति सीमित या बाधित रहती है वहां भी ये हाई मास्ट निर्बाध रूप से रोशनी प्रदान कर रहे हैं।

800 सोलर पंप से किसानों को मिली बड़ी राहत

कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जशपुर जिले में पिछले दो वर्षों में 800 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं, जिनसे सिंचाई सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। सोलर पंपों के उपयोग से किसानों को बिजली बिल से मुक्ति मिली है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि, भू-जल संरक्षण एवं संवर्धन, तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने जैसे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

आर्थिक संबल से आत्मविश्वास तक,
सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की महिलाएं

महतारी वंदन योजना केवल हर माह मिलने वाली 1000 रुपये की आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सपनों को पंख देने, उनके आत्मसम्मान को मजबूत करने और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बन गई है।

■ डॉ. दानेश्वरी संभाकर,
उप संचालक जनसंपर्क

किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तब मानी जाती है जब उसकी महिलाएं सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने लगें। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील पहल बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में यह योजना आज लाखों महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास, आर्थिक संबल और नई उम्मीदों का संचार कर रही है।

महतारी वंदन योजना केवल हर माह मिलने वाली 1000 रुपये की आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सपनों को पंख देने, उनके आत्मसम्मान को मजबूत करने और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बन गई है। प्रदेश के गांव-गांव से ऐसी प्रेरक कहानियां सामने आ रही हैं, जो बताती हैं कि छोटे-छोटे आर्थिक सहयोग से भी बड़े सामाजिक बदलाव संभव हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बस्तर में आयोजित वृहद महतारी वंदन कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से वर्चुअल संवाद कर अपने जीवन में आए बदलाव साझा किए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम खोडरी की श्रीमती अनीता साहू ने बताया कि पहले आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिवार चलाना मुश्किल था, लेकिन योजना से मिली राशि से उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और अनीता सिलाई सेंटर शुरू किया। आज वे सिलाई, खेती और मजदूरी के माध्यम से अपने परिवार को बेहतर जीवन दे रही हैं। उनका यह सफर संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक की प्रेरक कहानी बन गया है।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की श्रीमती मिथलेश चतुर्वेदी ने भी अपने जीवन का भावुक अनुभव साझा किया। पति के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। ऐसे कठिन समय में महतारी वंदन योजना ने उन्हें आर्थिक संबल दिया और उन्होंने ई-रिक्शा खरीदकर आजीविका का नया रास्ता चुना। आज वे आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही हैं और समाज में आत्मनिर्भर महिला की पहचान बना चुकी हैं।

कोरिया जिले की ग्राम डुमरिया निवासी श्रीमती बाबी राजवाड़े बताती हैं कि खेती-किसानी में मिलने वाली मासिक राशि उनके लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। वहीं ग्राम आमापारा की श्रीमती सुंदरी पैकरा इस राशि का उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई में कर रही हैं, जिससे उनके बच्चों के भविष्य को नई दिशा मिल रही है।

भरतपुर विकासखंड के ग्राम चांटी

की श्रीमती सविता सिंह की कहानी इस योजना की सार्थकता को और मजबूत करती है। उन्होंने महतारी वंदन योजना की राशि को बचाकर सिलाई मशीन खरीदी और सिलाई कार्य शुरू किया। आज वे गांव में कपड़ों की सिलाई कर नियमित आय अर्जित कर रही हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च स्वयं उठा रही हैं। उनकी सफलता ने गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है।

महतारी वंदन योजना का व्यापक प्रभाव प्रदेश के हर जिले में दिखाई दे रहा है। लगभग 69 लाख विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है और अब तक 25 किस्तों के माध्यम से 16 हजार 237 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए प्रदान की जा चुकी है। यह नियमित आर्थिक सहयोग महिलाओं के जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास ला रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह महिलाओं को केवल सहायता नहीं देती, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। महिलाएं इस राशि से छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं, बच्चों की पढ़ाई में निवेश कर रही हैं, खेती-किसानी को मजबूत बना रही हैं और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे परिवार, समाज और राज्य—तीनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। महिलाओं का कहना है कि पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब महतारी वंदन योजना ने उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने की ताकत दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में नई उम्मीद और नया आत्मविश्वास लेकर आई है।

सुरों की सम्राज्ञी-अब यादों में

आशा भोसले

ऐसे कलाकार कभी समाप्त नहीं होते, वे अपनी कृतियों में जीवित रहते हैं, अपने स्वरों में सांस लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के हृदय में गूंजते रहते हैं।

भारतीय संगीत का आकाश आज कुछ अधिक मौन, कुछ अधिक रिक्त प्रतीत होता है। स्वर की वह चंचल चिड़िया, जन-जन को चमत्कृत करने वाली आवाज जिसने दशकों तक हर हृदय में मधुरता के बीज बोए, आज भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच न हो, पर उसकी गूंज अनंत में विलीन होकर भी अमर बनी हुई है। आशा भोसले केवल एक गायिका नहीं थीं, वे भारतीय आत्मा की वह स्वर-लहरी थीं, जो हर संस्कृति, हर भावना और हर युग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहीं। वे एक बेमिसाल गायिका, अनगिनत लोगों की आशा एवं अभिलाषा की करिश्माई आवाज बनकर करीब 12000 गीतों का सृजन कर विश्व रिकार्ड बनाया। हृदयाघात के कारण उनका जाना केवल एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि भारतीय संवेदना के एक पूरे युग का अवसान है, परंतु यह अवसान भी किसी अंत का नहीं, बल्कि उस अमरत्व का संकेत है जहाँ कलाकार अपने शरीर से परे होकर अपनी कृति में जीवित रहता है। 'अभी न जाओ छोड़ कर' जैसे गीत आज करोड़ों हृदयों की सच्ची पुकार बन गए हैं। जिनकी आवाज ने विरह को भी मधुर बना दिया, आज उन्हीं के बिछोह में संसार भाव-विह्वल है। आशा जी की आवाज में एक अद्भुत जीवंतता थी, वह कभी किशोरी की चंचलता बन जाती तो कभी विरहिणी की करुण पुकार। उनके गीतों में जीवन की सम्पूर्णता समाहित थी- हंसी, आंसू, प्रेम, पीड़ा, श्रृंगार और भक्ति का ऐसा समन्वय जो दुर्लभ है। यही कारण है कि उनकी गूंज केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि विश्व के अनेक देशों में लोग उनके गीतों को गुनगुनाते रहे। यदि भारतीय संगीत को एक महासागर माना जाए तो आशा भोसले उसमें बहती वह नदी थीं, जिसने हर शैली को अपने भीतर समेट लिया। क्लासिकल से लेकर पॉप, जैज से लेकर गजल और कव्वाली तक, उन्होंने हर विधा में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। यह मानना कठिन है कि एक ही स्वर इतनी विविधताओं को इतनी सहजता से व्यक्त कर सकता है, पर आशाजी ने इसे संभव कर दिखाया। वे केवल गाती नहीं थीं, वे हर गीत को जीती थीं और यही कारण है कि उनके गीत केवल ध्वनि नहीं बल्कि अनुभूति बन जाते थे।

8 सितंबर 1933 को जन्मी आशाजी ने संगीत को साधना के रूप में जिया। लता मंगेशकर जैसी विराट प्रतिभा की छाया में अपनी अलग पहचान बनाना सरल नहीं था। अनेक प्रतिभाएँ उस छाया में दबकर गुमनामी में खो गईं, पर आशाजी ने संघर्ष को अपनी शक्ति बनाया। पिता दीनानाथ मंगेशकर से मिली संगीत की विरासत को उन्होंने अपने परिश्रम और साहस से विस्तार दिया। निजी जीवन के उतार-चढ़ाव, सामाजिक दबाव और प्रतिस्पर्धा के बीच भी उन्होंने अपने स्वर की लौ को कभी मंद नहीं होने दिया। ओ.पी. नैयर जैसे संगीतकारों के साथ उनका जुड़ाव उनके करियर का निर्णायक मोड़ बना और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी उपलब्धियाँ केवल लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहीं। ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित होना, पद्म विभूषण प्राप्त करना और गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड दर्ज कराना, यह सब उनकी दीर्घ साधना और असाधारण प्रतिभा के प्रमाण हैं। परंतु इन सबसे बढ़कर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वह प्रेम है, जो उन्हें श्रोताओं से मिला और जो आज भी उनके गीतों के माध्यम से जीवित है।

आशा जी के गीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समय की सीमाओं को लांघ जाते हैं। 'पिया तू अब तो आजा', 'दम मारो दम', 'चुरा लिया है तुमने', 'दिल चीज क्या है' जैसे अनगिनत गीत आज भी उतने ही ताजगी भरे लगते हैं जितने अपने समय में थे। उनके गीतों में केवल संगीत नहीं, बल्कि एक जीवंत आत्मा थी, जो हर शब्द को अर्थपूर्ण बना देती थी और उसे कालजयी बना देती थी। संगीत उनके लिए केवल कला नहीं, जीवन का श्वास था। जैसे बिना सांस के जीवन असंभव है, वैसे ही बिना संगीत के जीवन नीरस और अर्थहीन हो जाता है। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा का पोषण है। उनके हर गीत में कहीं न कहीं ईश्वर की स्तुति, जीवन की सार्थकता और भावनाओं की पवित्रता का स्पर्श मिलता है।

आज जब हम उन्हें स्मरण करते हैं, तो यह अनुभव होता है कि उनका जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि एक युग का समापन है। मो. रफी, मुकेश और किशोर कुमार के बाद आशा भोसले का जाना भारतीय संगीत की उस स्वर्णिम परंपरा के एक और दीप का बुझना है, जिसने इस देश की आत्मा को सुरों में पिरोया था। फिर भी यह भी उतना ही सत्य है कि ऐसे कलाकार कभी समाप्त नहीं होते, वे अपनी कृतियों में जीवित रहते हैं, अपने स्वरों में सांस लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के हृदय में गूंजते रहते हैं। मोहन भागवत द्वारा व्यक्त श्रद्धांजलि इस सत्य को और गहराई देती है कि आशा भोसले केवल एक गायिका नहीं थीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना की प्रतीक थीं। उनका योगदान केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से भारतीयता, संवेदनशीलता और जीवन के उत्सव को अभिव्यक्त किया। उनका जाना निस्संदेह एक अपूरणीय क्षति है, पर उनकी आवाज, उनकी लय, उनकी जीवंतता और उनकी आत्मा इस देश की माटी में सदैव गूंजती रहेगी। यही उनकी सच्ची अमरता है और यही हमारे लिए उनकी सबसे बड़ी विरासत है।

आशा भोसले का व्यक्तिगत जीवन जितना संघर्षमय रहा, उतना ही अदम्य साहस, जीवटता और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी था। एक संगीत-साधक परिवार में जन्म लेकर उन्होंने बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया, परंतु हर चुनौती को उन्होंने अपनी शक्ति में रूपांतरित किया।

जब आँखों की बात हो, तो पूरा परिवार एक ही नाम लेता है,

Shri Ganesh Vinayak Eye Hospital

भरोसा जो पीढ़ियों तक चले!

T3 Shri Ganesh Vinayak Eye Hospital
Team. Trust. Technology.

सुसज्जित है अत्याधुनिक मशीनों और
आधुनिक तकनीक से।

हर कोना रोशनी से रोशन:
20 Vision Centres – गाँव से शहर तक पहुँच

NABH द्वारा मान्यता प्राप्त –
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आई केयर नेटवर्क।

Numbers जो बोलते हैं खुद:
5.2 लाख आँखों की जाँच | 2.5 लाख+ सफल सर्जरी

भारत के अलग-अलग कोनों से प्रशिक्षित
विशेषज्ञ डॉक्टर करते हैं इलाज।

50+ टाई-अप्स – बीमा कंपनियाँ, सरकारी संस्थान,
TPA व प्राइवेट कंपनियाँ

यहां इलाज नहीं, एक भरोसा मिलता है – जो आंखों से दिल तक जुड़ता है।

Near Colors mall, Opposite to Ganga Diagnostic, Pachpedi Naka, New Dhamtari road, Raipur

www.sgveh.com 9644902896

All India Panchayat Parishad
अखिल भारतीय पंचायत परिषद
राष्ट्र पिता माहात्मा गाँधी
बलवंत राय मेहता
24 अप्रैल 2026 स्थापना दिवस
छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत परिषद
Chhattisgarh State Panchayat Parishad
विधानसभा अध्यक्ष
उपमुख्यमंत्री छ.ग
संरक्षक
प्रदेश सलाहकार
राष्ट्रीय संरक्षक
मा.नितिन गडकरी जी
केन्द्रीय मंत्री,सड़क परिवहन राजमार्ग
जल संसाधन भारत सरकार
मा.विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री छ.ग.
कार्यक्रम
समय-दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक दिनांक-24.04.2026
स्थान - पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर
घनश्याम प्रसाद यादव
प्रदेश संयोजक
नरेन्द्र पाण्डेय
प्रदेश मीडिया सह प्रभारी
-: कार्यालय :-
ई/एस, शताब्दी नगर, ST 7 तेलीबांधा रायपुर,
राजेंद्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत, 492001,8817171172